राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण मंगलवार 10 फरवरी 2026 वर्ष-9,अंक-18 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

चंद्रयान-4: इसरो को मिली बड़ी कामयाबी, खोज ली गई लैंडिंग की सुरक्षित जगह

श्रीहरिकोटा (एजेंसी)। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने अगले और अब तक के सबसे चुनौतीपूर्ण चंद्र मिशन चंद्रयान-4 की दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इसरो के स्पेस ऐप्लिकेशन सेंटर (एसएसी) ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उस सटीक स्थान की पहचान कर ली है, जहां चंद्रयान-4 को उतारा जाएगा। यह खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रयान-4 भारत का पहला रिटर्न मिशन होगा, जिसका लक्ष्य न केवल चांद पर उतरना है, बल्कि वहां से नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौटना भी है। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर द्वारा भेजी गई हाई-रिजोल्यूशन तस्वीरों का गहन विश्लेषण करने के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लगभग 1 वर्ग किलोमीटर के एक सुरक्षित क्षेत्र का चयन किया है। इस अध्ययन को वैज्ञानिकों की एक विशेष टीम ने अंजाम दिया है, जिन्होंने लैंडिंग के लिए चार संभावित स्थलों की समीक्षा की थी। जांच के बाद एमएम-4 नामक स्थान को सबसे उपयुक्त पाया गया है। मिशन की चुनौतियां और विशेषताएं चंद्रयान-4 मिशन तकनीक और जटिलता के मामले में पिछले मिशनों से काफी आगे है। इस मिशन में प्रोपल्सन मॉड्यूल के साथ-साथ डिसेंटर और असेंडर मॉड्यूल शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसफर मॉड्यूल और रीएंट्री मॉड्यूल भी इस मिशन का हिस्सा होंगे। मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह से मिट्टी और पत्थरों के नमूने एकत्र करना और उन्हें सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लाना है। यदि भारत इस मिशन में सफल रहता है, तो यह भविष्य के मानवयुक्त चंद्र मिशनों (गगनयान के अगले चरण) के लिए मील का पत्थर साबित होगा। लैंडिंग साइट की खासियत चुनी गई लैंडिंग साइट नॉविस माउंटेन पहाड़ी के पास स्थित है। पहाड़ी क्षेत्र के करीब होने के बावजूद, यह पैच काफी समतल है, जिससे लैंडर को नुकसान पहुंचने का खतरा न्यूनतम है। इस जगह की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहां सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है, जो सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों के लिए अनिवार्य है। साथ ही, यहां बड़े गड्ढों का अभाव है, जिससे रोवर को सतह पर चलने में आसानी होगी। यह क्षेत्र चंद्रयान-3 के लैंडिंग स्थल शिव-शक्ति पॉइंट से अधिक दूर नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस इलाके के गहरे गड्ढों में बर्फ या पानी के अवशेष मिल सकते हैं। यहां से लाए गए सैंपल्स से चंद्रमा के निर्माण और वहां मौजूद प्राकृतिक संसाधनों को समझने में वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को नई दिशा मिलेगी। चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद, अब पूरी दुनिया की नजरें इसरो के इस महत्वाकांक्षी रिटर्न मिशन पर टिकी हैं।

संसद और स्कूलों में बम की धमकी

नई दिल्ली (एजेंसी)। राजधानी दिल्ली के 9 स्कूलों को सोमवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी भरे ई-मेल मिले। मेल में दावा किया गया कि 13 फरवरी को दोपहर 1.11 बजे संसद में ब्लास्ट होगा और दिल्ली को खालिस्तान बना देंगे। ईमेल में आतंकी अफजल गुरु और पंजाब को खालिस्तान बताने का भी जिक्र था। धमकी के बाद स्कूलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक, सुबह अलग-अलग इलाकों के स्कूलों से इमरजेंसी कॉल आईं। इसके बाद फायर टेंडर, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड तुरंत मौके पर पहुंची। धमकी भरे ईमेल में लिखा है कि अफजल गुरु की याद में दिल्ली बनेगा खालिस्तान। 1:11 बजे पर धमाका होगा, 13 फरवरी को 1:11 बजे पर संसद में ब्लास्ट होगा। पंजाब खालिस्तान है। खालिस्तान नेशनल आर्मी। डीएफएस के एक अधिकारी ने कहा कि अब तक 9 स्कूलों ने बम की धमकी मिलने की सूचना दी है। सभी परिसरों की जांच की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ईमेल की लोकेशन और सोर्स पता करने के लिए साइबर टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। साथ ही राजधानी के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। अब तक किसी भी स्कूल से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है।

मणिपुर में फिर हिंसा, सशस्त्र उग्रवादियों ने कई मकानों में लगाई आग, कर्फ्यू लागू

-यह हिंसा तंगखुल नगा समुदाय के एक व्यक्ति पर हमले के बाद भड़की

इंफाल (एजेंसी)। मणिपुर के उखरुल जिले में एक बार फिर हिंसा का तांडव देखने को मिला। रविवार रात सशस्त्र उग्रवादियों ने लिटान सारेइखोंग क्षेत्र में कई मकानों में आग लगा दी। यह हिंसा तंगखुल नगा समुदाय के एक व्यक्ति पर हुए हमले के बाद उपजे तनाव का परिणाम बताई जा रही है। प्रशासन ने स्थिति को अनियंत्रित होते देख जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट में अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि रविवार शाम को जिले के लिटान गांव में दो आदिवासी समूहों ने पथराव किया, जिसके कारण प्रशासन को निषेधाज्ञा लागू करनी पड़ी।

परीक्षा पे चर्चा : गुरु पीएम मोदी का छात्रों को गुरुमंत्र...

कभी भी तकनीक का गुलाम नहीं बनना

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के दूसरे एपिसोड में देशभर से आए छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी कोयंबटूर से छत्तीसगढ़ पहुंचे और बच्चों से बात की। इसके बाद पीएम मोदी गुवाहाटी के अष्टलक्ष्मी पहुंचे। पीएम मोदी ने बच्चों से कहा कि कभी भी तकनीक का गुलाम नहीं बनना चाहिए। बल्कि तकनीक का इस्तेमाल केवल और केवल अपनी क्षमता बढ़ने के लिए करना चाहिए। परीक्षा पे चर्चा के दूसरे एपिसोड में पीएम मोदी ने बच्चों को पढ़ने के साथ, लिखकर प्रैक्टिस करने की सलाह दी। साथ ही बच्चों से कहा कि पहले निडर बनो फिर लीडर बन जाओगे।

पीएम मोदी ने छात्रों को पढ़ाई में कमजोर अपने क्लासमेट्स की मदद करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि तेज छात्रों को उन कमजोर छात्रों से दोस्ती करनी चाहिए और उन्हें टॉपिक समझाने चाहिए। दूसरों को पढ़ाने से खुद भी बेहतर सीखने में मदद मिलती है।

परीक्षा के समय तनाव कैसे कम करें

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी से छात्रों ने पूछा कि तनाव कैसे कम करे, इस पर पीएम मोदी ने कहा कि आप पुरानी परीक्षा के दिनों को याद कीजिए। जब आप पुरानी परीक्षाओं को याद करते हैं, तब आपको लगेगा उस समय भी तनाव था, लेकिन जब वह परीक्षा देकर आ गया, तब कुछ नहीं था। ऐसा होता है ना। परीक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज होती है कि आप पेपर सॉल्व करने की आदत डालें। लिखने की आदत डालें। अगर खुद आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहने वाले हैं, तब आपको कभी तनाव नहीं होगा।

आप घूमने जा रहे हैं, तब पहले अपनी तहसील में ये देखने की कोशिश करें कि आप कहां जा सकते हैं, फिर जिला, फिर राज्य। कहने का मतलब ये है कि आप जहां भी घूमें एक छात्र की नजर से घूमें ताकि आप लगातार कुछ सीख

सकें।

पीएम मोदी ने बच्चों से कहा कि पहले निडर बनो, जो काम है, मन में तय करो कि कोई ओर करे या ना करे मैं करुंगा। जब आप ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं तब आप देखना कि अपने आप लीडरशिप क्वालिटी तैयार हो जाएगी। मान लीजिए कहीं कचरा है और उस कचरे को आपने उठा लिया, तब आपकों देख रहे 4 लोग भी ऐसा ही करने वाले है।

इसके पहले 6 फरवरी को पहले एपिसोड में पीएम मोदी ने दिल्ली स्थित पीएम आवास पर बच्चों से चर्चा की थी। असम के गमछे पहने थे और उनके सवालों के जवाब भी दिए थे। पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स को विदेशी चीजें छोड़कर स्वदेशी चीजें अपनाने की सलाह दी थी।

सेशेल्स के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी ने किया 175 मिलियन डॉलर के आर्थिक पैकेज का ऐलान

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के बीच दिल्ली में सोमवार को मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 175 मिलियन डॉलर के आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने आर्थिक पैकेज का ऐलान कर कहा, हम अपने आर्थिक सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए मौकों की तलाश जारी रखने पर सहमत हैं। लोकल करेंसी में व्यापार बढ़ाने के साथ-साथ हम फिनटैक और डिजिटल समाधान में भी अग्रसर हो रहे है। विकास साझेदारी भारत-सेशेल्स संबंधों की मजबूत नींव रही है। वहीं सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. हर्मिनी ने कहा, मैं आज सेशेल्स रिपब्लिक के राष्ट्रपति के तौर पर भारत के अपने पहले राजकीय दौरे पर आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों को मेरे आने पर दी गई गर्मजोशी भरी मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद देता हूं। यह दौरा सेशेल्स और भारत के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती और आपसी सम्मान को दिखाता है, खासकर इसलिए क्योंकि यह साल हमारे रिश्तों में एक अहम पड़ाव है। इसी साल जून में, सेशेल्स और भारत अपने डिप्लोमैटिक संबंधों की गोल्डन जुबली मनाएंगे।

उन्होंने कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और ज्यादा सहयोग के मौकों पर केंद्रित कर व्यापार और प्राइवेट सेक्टर के पहलू की भी जांच की गई। इन लिंकेज को बेहतर बनाना, दोनों देशों के बीच अच्छी नीयत को लगातार आर्थिक गतिविधि में बदलने के लिए जरूरी है। राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा, हमारी बातचीत में आर्थिक जुड़ाव और विकास के समर्थन पर खास ध्यान दिया गया। हमने प्रोजेक्ट-बेस्ड सपोर्ट और लाइन ऑफ क्रेडिट सहित सही विकास सहयोग इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए प्रायोरिटी इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। हिंद महासागर के तौर पर मैरीटाइम सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता हमारे संबंधों का मुख्य केंद्र है।

हंगामे के चलते 13 मिनट में स्थगित हुई लोकसभा की कार्यवाही

राहुल गांधी को बोलने नहीं देने पर विपक्ष ने किया जबरदस्त विरोध

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली, (ईएमएस)। संसद के बजट सत्र के नौवें दिन मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही भारी हंगामे के बीच महज 13 मिनट ही चल सकी। विपक्ष ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने का मौका न दिए जाने का मुद्दा उठाया, जिसके बाद सदन में शोरगुल बढ़ गया और कार्यवाही पहले 12 बजे तक के लिए, फिर 2 बजे तक के लिए और फिर मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

इससे पहले लोकसभा में राहुल गांधी ने आसंदी की ओर इशारा करते हुए कहा कि सत्र शुरू होने से करीब एक घंटे पहले विपक्षी नेता स्पीकर के कक्ष में गए थे। राहुल का दावा था, कि स्पीकर ने उन्हें बजट पर चर्चा से पहले बोलने का आश्वासन दिया था। राहुल गांधी ने कहा, स्पीकर ने कमिट किया था कि मुझे बोलने दिया जाएगा, लेकिन अब आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुझे बोलने दिया जाएगा या नहीं। दोपहर तीन बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, उस समय लोकसभा अध्यक्ष की आसंदी पर भाजपा सांसद संध्या राय बैठी थीं।

रिजिजू बोले- कोई कमिटमेंट नहीं किया

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा, कि वह स्वयं स्पीकर के कक्ष में मौजूद थे और वहां किसी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं किया गया था। रिजिजू ने कहा कि स्पीकर की ओर से राहुल गांधी को बोलने को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।

आसंदी ने नियमों का दिया हवाला

इस पर संध्या राय ने राहुल गांधी से कहा कि उनकी ओर से किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा के लिए कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि राहुल गांधी बजट पर चर्चा करना चाहते हैं, तो उन्हें नियमों के अनुसार अपनी बात रखनी चाहिए।

जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने किया हंगामा

इस जवाब से असंतुष्ट होने के बाद विपक्षी सांसदों ने सदन में जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष का आरोप था कि जानबूझकर नेता प्रतिपक्ष को बोलने से रोका जा रहा है। लगातार नारेबाजी और व्यवधान के कारण लोकसभा की कार्यवाही को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष

इस बीच राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि विपक्ष इस विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है। साथ ही इसके लिए सदन में 14 दिन पहले लिखित नोटिस देना अनिवार्य है।

बीजेपी के ये अच्छे दिन आरएसएस की वजह से ही आए: मोहन भागवत

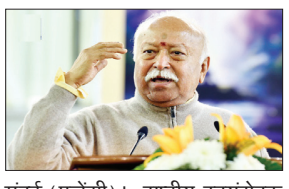

मुंबई (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी को लेकर बड़ी लकीर खींच दी है। 2024 के आम चुनाव में तत्कालीन अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम आरएसएस के बिना भी चुनाव में जीत सकते हैं। इसे लेकर संघ कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष फैल गया था। अब सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि बीजेपी के ये अच्छे दिन आरएसएस के चलते ही आए हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन के लिए आरएसएस ने प्रतिबद्धता दिखाई थी और जिसने इसका साथ दिया, उसे फायदा मिला। इस तरह उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि संघ के नेतृत्व में चले राम मंदिर आंदोलन का फायदा बीजेपी को चुनाव में भी मिला।

पाकिस्तान की गीदड़भभकी फेल! आईसीसी ने नहीं मानी एक भी शर्त, मोहसिन नकवी को 24 घंटे का अल्टीमेटम

नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने भारतीय टीम के साथ द्विपक्षीय श्रृंखलाओं को फिर से शुरू करने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की मांग को खारिज कर दिया है। यह ध्यान देने योग्य है कि पीसीबी ने ये मांगें तब रखीं जब पाकिस्तान सरकार ने चल रहे टी20 विश्व कप 2026 में भारत के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद एक बैठक हुई थी। यह उल्लेखनीय है कि टी20 विश्व कप के बहिष्कार विवाद के मद्देनजर पीसीबी ने आईसीसी के सामने तीन मांगें रखीं; बोर्ड ने भारत के साथ द्विपक्षीय श्रृंखलाओं को फिर से शुरू करने की मांग की, साथ ही भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच त्रिकोणीय श्रृंखला की भी मांग की।

समीक्षा के दौरान अमित शाह ने भरी हुंकार कहा- अगले माह नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा देश

रायपुर (एजेंसी)। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति पर एक उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ-साथ केंद्रीय गृह सचिव, आईबी निदेशक और सीआरपीएफ, एनआईए, बीएसएफ व आईटीबीपी के महानिदेशक भी शामिल हुए। इसके अलावा, नक्सल प्रभावित राज्यों जैसे तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र के गृह सचिव व पुलिस महानिदेशक भी मौजूद रहे, जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए अमित शाह ने एक बड़ा लक्ष्य साझा किया और विश्वास जताया कि 31 मार्च 2026 से पहले भारत पूरी तरह से नक्सलवाद के अभिशाप से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार की सुरक्षा-केंद्रित ठोस रणनीति, मजबूत बुनियादी ढांचे का विकास, नक्सलवाद के वित्तीय

नेटवर्क पर कड़ा प्रहार और एक प्रभावी आत्मसमर्पण नीति के कारण आज सकारात्मक परिणाम धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि माओवाद के खिलाफ यह लड़ाई बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने राज्यों को निर्देश दिया कि वे आपस में ऐसा तालमेल बिठाएं जिससे बचे हुए नक्सली सुरक्षा बलों के दबाव में एक राज्य की सीमा से भागकर दूसरे राज्य में शरण न ले सकें। शाह ने छत्तीसगढ़ के बदलते परिदृश्य की सराहना करते हुए कहा कि जो राज्य कभी नक्सली हिंसा का गढ़ माना जाता था, वह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के चलते विकास का नया केंद्र बन चुका है। उन्होंने बताया कि अब छत्तीसगढ़ के युवा हिंसा का रास्ता छोड़ खेल, फॉरेंसिक और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। गृह मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि नक्सलवाद ने कई पीढ़ियों को गरीबी और अशिक्षा के अंधेरे में धकेला है, लेकिन अब विकास के समान अवसर हर प्रभावित क्षेत्र तक पहुँच रहे हैं। यह सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे।

कांग्रेस पर बिफरे केंद्रीय मंत्री रिजिजू... कांग्रेस संसद को चलने नहीं देना चाहती

नई दिल्ली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही बाधित करने के लिए कांग्रेस सांसदों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में अभद्र व्यवहार का आरोप लगाकर कांग्रेस पार्टी पर कार्यवाही को बाधित करने का आरोप लगाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा संबंधी चेतावनी देने पर प्रतिक्रिया देकर केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस सांसदों का आचरण अस्वीकार्य है। यह घटना स्पीकर बिरला द्वारा गुरुवार को दिए गए उस बयान के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ कांग्रेस सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की सीट के पास जाकर अभूतपूर्व घटना को अंजाम देने की सूचना के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को सदन में उपस्थित न होने की सलाह दी थी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोक सके। इस पर प्रतिक्रिया देकर केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष बिरला के कक्ष में कांग्रेस सांसदों के व्यवहार की निंदा करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के सदन में प्रवेश करते ही कांग्रेस ने हंगामा करने की योजना बनाई थी। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी के सदन में आते ही उनसे कागजात छीनने की योजना बनाई थी। रिजिजू ने कहा कि संसद गुंडागर्दी का स्थान नहीं है। हर चीज की एक सीमा होती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार सदन को सुचारू रूप से चलाना चाहती है, लेकिन व्यवधान संसदीय कार्य में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सदन चलाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस सदन को चलने नहीं देना चाहती, तब अन्य सांसदों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक अलग बयान में, रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस लगातार व्यवधान के कारण नहीं हो सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में कांग्रेस नेतृत्व जानबूझकर कार्यवाही में बाधा डाल रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस नहीं हो सकी। मुझे लगता है कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता सदन को चलने नहीं देना चाहते। अध्यक्ष भी कांग्रेस सांसदों के व्यवहार से आहत हैं।

पाक एजेंट आरोप पर बोले गौरव गोगोई- मुझे मजबूर किया गया तो चुप नहीं रहूंगा

गुवाहाटी (एजेंसी)। असम में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर लगाए गए 'पाकिस्तान कनेक्शन' के आरोपों पर अब गोगोई ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान को न सिर्फ अस्वीकार्य बताया, बल्कि इसे राजनीतिक शिष्टाचार की सभी सीमाओं को पार करने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि मुझे मजबूर किया तो फिर मैं चुप नहीं रहूंगा।

दरअसल, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने गौरव गोगोई की वर्ष 2013 की पाकिस्तान यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उनके वीजा में लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जाने की अनुमति थी, जबकि उन्होंने तक्षशिला का दौरा किया, जो पंजाब के रावलपिंडी जिले में स्थित है। मुख्यमंत्री सरमा ने यह भी कहा कि रावलपिंडी एक हाई-सिक्योरिटी क्षेत्र है, जहां पाकिस्तानी सेना का जनरल हेडक्वार्टर (जीएचक्यू) मौजूद है और वहां आम नागरिकों का प्रवेश आसान नहीं होता। ऐसे में यह दौरा किसी संस्थागत व्यवस्था के बिना संभव नहीं हो सकता। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताया।

इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिस एसआईटी रिपोर्ट का हवाला दिया था, उसे छह महीने तक दबाकर रखा गया, क्योंकि सरकार उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश करने में असफल रही। गोगोई ने सवाल किया कि यदि यह मामला वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा था, तो मुख्यमंत्री इतने समय तक चुप क्यों बैठे रहे। गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि असम में कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, जब हमने मुख्यमंत्री के परिवार के पास कथित रूप से 12 हजार बीघा जमीन होने का मुद्दा उठाया, तभी से यह पूरा नाटक शुरू हुआ। उन्होंने पाकिस्तान से किसी भी तरह के संबंधों के दावों को सिरे से खारिज किया।

मुख्यमंत्री द्वारा उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न और पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के साथ संबंधों के आरोप पर भी गोगोई ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी काम के सिलसिले में पाकिस्तान गई थीं और वह 2013 में 10 दिन की सामान्य यात्रा पर उनके साथ गए थे, जिसमें कुछ भी गुप्त या गैरकानूनी नहीं था। गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री पर उनके नाबालिग बच्चों को राजनीति में घसीटने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई नेताओं के बीच होनी चाहिए, बच्चों को इसमें शामिल करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, मुझे ऐसी स्थिति में मजबूर न करें, जहां मुझे जवाब देना पड़े। गोगोई ने यह भी कहा कि यह मामला इतना गंभीर है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

एपस्टिन फाइल्स का उजागर होना डीप स्टेट की करतूत?

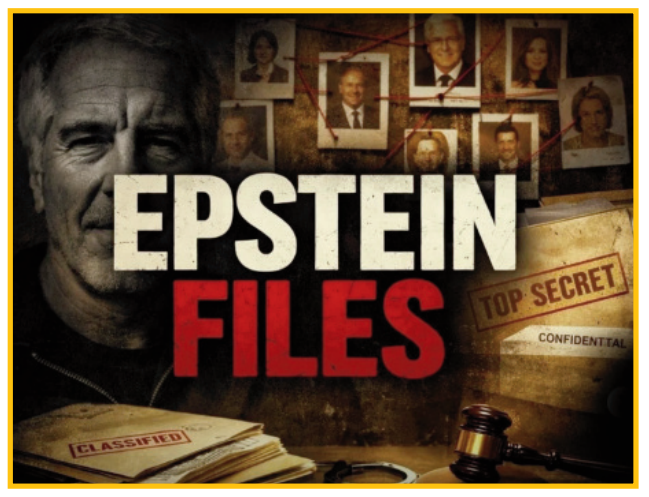

कुलदीप शर्मा

वरिष्ठ पत्रकार/ विश्लेषक

अगर आप ध्यान दें, तो इन फाइलों में सिर्फ़ 'सच' नहीं है बल्कि इसमें हज़ारों 'फ़र्ज़ी' शिकायतें भी शामिल कर दी गई हैं। इसका मकसद यही दिखता है कि जब सच और झूठ को मिक्सी में पीस दिया जाता है या फिर किसी विषय पर जानकारी अत्यधिक हो जाती है तो जनता 'सच' पर भी यकीन करना छोड़ देती है। जैसे अब जितने भी बड़े लोगों जैसे ट्रंप और बिल गेट्स ने इसे झुठला दिया। भले ही इससे इन सबकी बदनामी हुई, लेकिन सजा किसी को नहीं हुई। 'सब नंगे हैं' बोलकर असली गुनहगारों को भीड़ में छिपा दिया गया या फिर माइकल जैक्सन,स्टीफन हॉकिंग, क्लिंटन या प्रिंस एंड्रयू जैसे नाम दिखाकर उलझाया जा रहा है, लेकिन थोड़ा गहरी नजर से देखने पर महसूस होता है कि यह लिस्ट 'सच' बताने के लिए नहीं, बल्कि 'असली सच' को हमेशा के लिए दफ्न करने के लिए आई है।

पिछले कुछ दिनों से एपस्टिन फाइल्स बहुत चर्चा में बनी हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि यह अब तक के इतिहास में उजागर किया गया सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल और घिनौना सेक्स स्कैंडल है। जानकारी के अनुसार इसमें पांच की मासूम ब'चियों से लेकर चौदह साल तक की बालिकाओं के साथ केवल दुष्कर्म ही नहीं किया गया बल्कि उन्हें चोट पहुंचाने के साथ साथ उन्हें मार कर खा लिया गया। ऐसी घिनौनी कार्रवाई को अंजाम देने और यह सब करने वाले कोई और नहीं बल्कि दुनिया के बेहद अमीर, ताकतवर और हाई क्लास व्यक्ति रहे थे, जो दिन के उजाले में बेहद शफीफ इंसान के रूप में दिखाई देते रहे थे, लेकिन रात के अंधेरे में शैतान बन जाते थे। एपस्टिन फाइल्स की जारी हुई सामग्री में 30 लाख से 'यादा पन्नों के रिकॉर्ड के साथ 2,000 से अधिक वीडियो और करीब 1 लाख 80 हजार तस्वीरें सार्वजनिक करने की बात सामने आई है।

एपस्टिन फाइल्स की चर्चा के बाद यह जो कुछ भी उजागर हुआ है, वह तस्वीर का एक पहलू है। इस तस्वीर का दूसरा पहलू किसी दूसरी ही तरफ इशारा करता है। इसमें पहला तो खुद एपस्टिन का इस तरह का सेक्स रैकेट को चलाने का मकसद क्या रहा था।

और दूसरा यह कि 2019 में खत्म हो चुके इस केस को पिछले साल 2025 में दुनिया के सामने दुबारा फिर से उजागर करने का मकसद क्या है? जानकारी के अनुसार जेफ्री एपस्टिन एक यहूदी था, जो अपने प्राइवेट आइलैंड पर दुनिया भर के बड़े बड़े राजनेताओं और बिजनेसमैन सहित बड़े बड़े वैज्ञानिकों, जिसमें स्टीफन हॉकिंस जैसे अपंग वैज्ञानिक भी शामिल थे के अलावा बड़ी रिसर्चों या प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को अय्याशी के नाम पर आमंत्रित करता था और यहां बुलाकर उनकी गंदी हरकतों के सबूत इकट्ठा करता था। सरसरी तौर पर देखने पर यह सामान्य सी बात लगती है, लेकिन गहराई से देखने पर यह कोई जासूसी ट्रैप सा लगता है। कहने का मतलब यह है कि यह कोई हवस मिटाने का खेल नहीं, बल्कि यह 'ब्लैकमेल' का धंधा था। यह केवल अय्याशी का कोई अड्डा नहीं था, बल्कि यह एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। जानकारी के अनुसार जेफ्री एपस्टिन की पार्टनर घिसलेन मैक्सवेल के पिता रॉबर्ट मैक्सवेल का कनेक्शन इज़राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़ा हुआ बताया गया है यानी अय्याशी की इन कारगुज़ारियों का मकसद साफ था कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों (नेताओं/साइंटिस्ट्स) को पहले ऐसे 'हनी ट्रैप' में फंसाना, फिर उनकी इन सबके वीडियो बनाना और बाद में इनके दम पर उनसे अपनी मर्जी के फैसले करवाना।

गौर करने वाली बात यह है कि अब जिस तरह से एक खत्म हो चुके मामले को अचानक दुबारा खोला गया है वह हैरान करने वाला इसलिए माना जा सकता है कि इसमें खुद मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सहित पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटल और अमेरिकी बिलेनियर बिल गेट्स का नाम शामिल है। यह अपने आप में बहुत अजीब है। ऐसा लगता है, जैसे जो हुआ वह भी एक साजिश थी और अब जो हो रहा है वह भी एक साजिश का हिस्सा है। साजिश भी इतनी बड़ी कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति और दुनिया के सबसे धनी लोगों में शामिल बिल गेट्स की भी इसमें नहीं चली और उनको भी इस चाल का मोहरा बनना पड़ा। देखा जाए तो एपस्टिन फाइल्स का खुलना एक तरफ 'स'चाई की जीत' लग सकता है तो दूसरी तरफ यह एक भ्रम है। सच तो यह है कि इन फाइलों को 'मंज़ूरी' इसलिए दी गई, क्योंकि अब इनका इस्तेमाल एक 'हथियार' की तरह किया जा रहा है।

अगर आप ध्यान दें, तो इन फाइलों में सिर्फ़ 'सच' नहीं है बल्कि इसमें हज़ारों 'फर्जी' शिकायतें भी शामिल कर दी गई हैं। इसका मकसद यही दिखता है कि जब सच और झूठ को मिक्सी में पीस दिया जाता है या फिर किसी विषय पर जानकारी अत्यधिक हो जाती है तो जनता 'सच' पर भी यकीन करना छोड़ देती है। जैसे अब जितने भी बड़े लोगों जैसे ट्रंप और बिल गेट्स ने इसे झुठला दिया। भले ही इससे इन सबकी बदनामी हुई, लेकिन सजा किसी को नहीं हुई। 'सब नंगे हैं' बोलकर असली गुनहगारों को भीड़ में छिपा दिया गया या फिर माइकल जैक्सन,स्टीफन हॉकिंग, क्लिंटन और प्रिंस एंड्रयू जैसे नाम दिखाकर उलझाया जा रहा है, लेकिन थोड़ा गहरी नजर से देखने पर महसूस होता है कि यह लिस्ट 'सच' बताने के लिए नहीं, बल्कि 'असली सच' को हमेशा के लिए दफ्न करने के लिए आई है। गौर करने वाली बात यह है कि कीचड़ उन पर उछाला गया जो या तो मर चुके हैं (हॉकिंग) या जिनका करियर ही खत्म हो चुका है जैसे क्लिंटन या फिर एंड्रयू जैसे लोग हैं। ये ऐसे 'प्यादे' हैं, जिनकी अब व्यवस्था को आवश्यकता नहीं रही है। एपस्टीन फाइलों में दुनिया भर के वैज्ञानिकों की एक आंशिक सूची दी गई है। इनमें कई नोबेल पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं और हार्वर्ड, एमआईटी, येल जैसे विश्वविद्यालय आदि से भी संबद्ध रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग को छोड़ दिया जाए तो बाकी अधिकांश अमेरिकी नागरिक बताए जाते हैं। इस सूची में स्टीफन हॉकिंग (सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी), मार्विन मिन्स्की (कंप्यूटर वैज्ञानिक, एआई के अग्रदूत), लॉरेंस क्रॉस (भौतिक विज्ञानी/कॉस्मोलॉजिस्ट), नोम चॉम्स्की (भाषाविद्, संज्ञानात्मक वैज्ञानिक), एरिक लैंडर (गणितज्ञ, आनुवंशिकीविद्), किप थॉर्न (भौतिक विज्ञानी, नोबेल पुरस्कार विजेता), फ्रैंक विल्चेक (भौतिक विज्ञानी, नोबेल पुरस्कार विजेता), मरे गेल-मैन (भौतिक विज्ञानी, नोबेल पुरस्कार विजेता), लिसा जे. रैंडल (भौतिक विज्ञानी), मार्टिन ए. नोवाक (गणितीय जीवविज्ञानी), कोरीना टार्निटा (विकासवादी जीवविज्ञानी/पारिस्थितिकीविद्), डेविड गेलर्न्टर (कंप्यूटर वैज्ञानिक), रॉबर्ट ट्राइवर्स (विकासवादी जीवविज्ञानी), स्टीवन पिंकर (संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक/भाषाविद्), जेराल्ड एडेलमैन (प्रतिरक्षाविज्ञानी, नोबेल पुरस्कार विजेता), ऑलिवर सैक्स (तंत्रिका विज्ञानी), स्टीफन जे. गोल्ड (विकासवादी जीवविज्ञानी), लैरी समर्स (हार्वर्ड के अध्यक्ष), निकोलस क्रिस्टाकिस (समाजशास्त्री, नेटवर्क अध्ययन) आदि के नाम उजागर हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मौजूदा समय में हो रहे वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा तय करने में यही लोग निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं और एपस्टीन चुनिंदा शोध क्षेत्रों में धन प्रवाहित कर रहा था या फिर उन विषयों में जिन्हें वह स्वयं आगे बढ़ाना चाहता था, या जिनके लिए उसे ऊपर से निर्देश मिल रहे थे। कहने का मतलब यह है कि जिस किसी के पास भी पैसा है, तो वह विज्ञान को भी नियंत्रित कर सकता है, बस शोध के लिए धन की दिशा तय कर दीजिए। जो कोई भी अकादमिक दुनिया में करियर बनाना चाहता है, उसे धन के इस प्रवाह के साथ खुद को ढालना पड़ता है। इससे यह माना जा सकता है कि विज्ञान कभी भी पूरी तरह मुक्त जिज्ञासा (ओपन-इन्क्वायरी) की प्रणाली नहीं रहा। वैज्ञानिक शोध की शुरुआत में इसे कथित रूप से कैथोलिक चर्च ने दिशा दी बताई गई, बाद में किसी अन्य चर्च ने। देखने वाली बात यह है कि अब इसे वे लोग नियंत्रित करते हैं, जिनके पास निजी द्वीप हैं। पहले कोई इस पर विश्वास नहीं करता था। आज भी अधिकांश लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो आज सत्ता में हैं, उनके नाम कहाँ हैं? वे वीडियो टेप्स कहाँ हैं, जो एपस्टिन के हर कमरे में रिकॉर्ड होते थे? ऐसा लगता है, इसमें डीप स्टेट का हाथ है, जो पूरी दुनिया की इकानॉमी और ताकत को वश में करना चाहता है। डीप स्टेट इतना ताकतवर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी उसके सामने बेबस नजर आते हैं और पूरी दुनिया में अपना तमाशा बनते देखने को मजबूर हैं, क्योंकि वे इस मामले में कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं।

देश के कुछ बड़बोले नेताओं ने एपस्टिन फाइल्स के खुलासे से पहले बड़े जोर शोर से यह घोषणा कर देने से परहेज नहीं किया था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। एपस्टिन फाइल्स के माध्यम से प्रधानमंत्री को भी निशाने पर लिया गया और बार बार उनका नाम इस मामले में उछाला गया है, लेकिन इस मामले अब तक ऐसा कुछ नहीं मिल सका है कि प्रधानमंत्री की बेदाग छवि पर कोई अंगुली उठाई जा सके। इस मामले में भारत के विदेश मंत्रालय ने उन रिपोर्टों को खारिज किया है, जिनमें तथाकथित जेफ्री एपस्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी और उनके इजरायल दौरे का संदर्भ होने की बात कही गई थी। मंत्रालय ने इन संदर्भों को 'दोषी ठहराए गए अपराधी की घटिया मनगढ़ंत बातें' बताते हुए कहा कि इन्हें 'पूरे तिरस्कार के साथ' खारिज कर दिया जाना चाहिए। मंत्रालय के मुताबिक उसने 'तथाकथित एपस्टीन फाइल्स' से जुड़े एक ईमेल संदेश के बारे में रिपोर्टें देखी हैं, जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजरायल दौरे का जिक्र है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री के इजरायल के आधिकारिक दौरे के तथ्य के अलावा, ईमेल में किए गए बाकी संकेत या इशारे दोषी ठहराए गए अपराधी की 'घटिया मनगढ़ंत बातें' भर हैं, जिन्हें पूरे सिरे के साथ खारिज कर दिया जाना ही उपयुक्त होगा।

संपादकीय

किसानों की आशंकाएं

बीते शनिवार जारी किए गए भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के प्रारूप को लेकर उठ रहे सवालों ने फिर उस मूलभूत सवाल को पुख्ता किया है कि मुक्त व्यापार समझौते की कीमत कौन चुकाएगा? साथ ही यह भी कि इसका लाभ किसे मिलेगा? इस समझौते से जुड़ी आशंकाओं को लेकर कुछ किसान संगठन आगामी 12 फरवरी को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। निस्संदेह, उनकी आशंकाएं सिर्फ सोयाबीन तेल, सूखे अनाज और सेब पर आयात शुल्क में छूट को लेकर ही नहीं हैं, बल्कि विश्वास, पारदर्शिता और भारतीय कृषि के भविष्य को लेकर भी हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार दावा कर रही है कि किसान हितों की रक्षा के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। निस्संदेह, कागजों पर तो ये आश्वासन राहत देने वाले लगते हैं, लेकिन व्यवहार में किसानों की आशंकाओं से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। उल्लेखनीय है कि यूरोपीय संघ व न्यूजीलैंड के साथ हुए पिछले मुक्त व्यापार समझौतों के कारण सस्ते आयात में भारी वृद्धि हुई, फलतः कमजोर किसानों की दशा खराब हुई। निर्विवाद रूप से भारी सब्सिडी प्राप्त अमेरिकी सेब से हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के सेब उत्पादकों के लिए मुकाबला करना चुनौतीपूर्ण होगा। हिमाचल के सेब उत्पादक संगठनों का कहना है कि अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क पचास से 25 प्रतिशत करना व न्यूनतम आयात मूल्य 50 से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम करने से यह स्वदेशी प्रीमियम सेवा के दाम पर बाजार में बिकने लगेगा। जिसके चलते भारतीय उपभोक्ता समान मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले अमेरिकी सेब को तरजीह देंगे। साथ ही सेब का कोल्ड स्टोरेज में संग्रह करना अलाभकारी हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार का दावा है कि कृषि और दुग्ध उद्योग संरक्षित रहेंगे। जबकि संयुक्त समझौते में कृषि और खाद्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर शुल्क कम करने और गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने की बात कही गई है। कम आय, बढ़ती लागत और बढ़ते कर्ज से जूझ रहे किसानों को इन गंभीर मुद्दों पर स्पष्टता चाहिए। यही वजह है कि कई किसान संगठनों, विपक्षी दलों और कुछ राज्य सरकारों ने मांग की है कि इस समझौते का पूरा विवरण संसद के समक्ष रखा जाए। निस्संदेह, यह मांग तार्किक है क्योंकि व्यापार समझौते भी घरेलू कानूनों की तरह ही आजीविका को गहराई तक प्रभावित करते हैं। कृषि विशेषज्ञ मान रहे हैं कि मजबूत घरेलू समर्थन, उचित मूल्य, सब्सिडी, बुनियादी ढांचे और जोखिम संरक्षण दिए बिना, बाजारों को खोलने के कदम छोटे और सीमांत किसानों पर भारी पड़ सकते हैं। इसी फिक्र के चलते हड़ताल एक चेतावनी है। यदि सरकार का मानना है कि यह समझौता वास्तव में किसानों के हितों को प्राथमिकता देता है तो उसे पारदर्शिता, संसदीय बहस और सार्थक परामर्श के माध्यम से इसे साबित भी करना चाहिए। अन्यथा, सुधारों की कहानी एक बार फिर देश के अन्नदाता की चिंताओं को दूर करने में विफल रहेगी। इसी तरह देश के सेब उत्पादकों को भी आश्वस्त करना होगा कि उनके सेब की खुशबू बरकरार रहेगी।

पोषण सुरक्षा और टिकाऊ कृषि का प्रभावी साधन हैं दालें

(लेखक- योगेश कुमार गोयल/)

(विश्व दलहन दिवस (10 फरवरी) पर विशेष)

हर साल 10 फरवरी को मनाया जाने वाला 'विश्व दलहन दिवस' हमें यह सोचने का अवसर देता है कि जिन दालों को हम रोजमर्रा के भोजन का साधारण हिस्सा मान लेते हैं, वे वास्तव में मानव सभ्यता और प्रकृति के बीच संतुलन की एक गहरी कड़ी हैं। खेतों से लेकर थाली तक की यह यात्रा केवल भोजन भर की नहीं है बल्कि इसमें पोषण, पर्यावरण, कृषि और भविष्य की खाद्य सुरक्षा के सूत्र छिपे हैं। वर्ष 2026 की आधिकारिक थीम 'विश्व की दलहनः सादगी से उत्कृष्टता की ओर' इसी सच्चाई को रेखांकित करती है कि छोटे से दिखने वाले बीज किस तरह वैश्विक समाधान बनकर उभर रहे हैं। यह दिवस खाद्य एवं कृषि संगठन के नेतृत्व में विश्वभर में मनाया जाता है। दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस की घोषणा के बाद से 2019 से यह निरंतर मनाया जा रहा है। इसकी प्रेरणा 2016 में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष से मिली थी, जिसने पहली बार वैश्विक मंच पर यह स्पष्ट किया कि दालें केवल पारंपरिक भोजन नहीं, पोषण सुरक्षा और टिकाऊ कृषि का प्रभावी साधन हैं।

दलहन, यानी फलीदार पौधों से प्राप्त सूखे और खाने योग्य बीज, सदियों से मानव आहार का आधार रहे हैं। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में ये भोजन की रीढ़ रहे जबकि आधुनिक समय तक कुछ क्षेत्रों में इन्हें साधारण या कम मूल्य वाला भोजन समझा गया लेकिन पोषण विज्ञान ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है। आज यह स्वीकार किया जा चुका है कि दालें उच्च गुणवत्ता वाले पौध-आधारित प्रोटीन का उत्कृष्ट स्रोत हैं। इनके साथ मिलने वाला आहार फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है और हृदय रोगों के जोखिम को कम करता है। आयरन, जिंक, फोलेट, मैग्नीशियम और बी-विटामिन्स जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व इन्हें हर आयु वर्ग के लिए उपयोगी बनाते हैं। कम वसा और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण ये आधुनिक जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती हैं।

पर्यावरण की दृष्टि से दालों का महत्व और भी व्यापक है। इनमें मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने की प्राकृतिक क्षमता होती है, जिससे खेतों की उर्वरता बढ़ती है और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है। अन्य फसलों की तुलना में इन्हें कम पानी की जरूरत पड़ती है और इनका कार्बन फुटप्रिंट भी कम होता है। यही कारण है कि बदलते जलवायु परिदृश्य में दलहन को जलवायु-अनुकूल और भविष्य की फसल माना जा रहा है। सीमित संसाधनों और अनिश्चित मौसम के दौर में ये फसलें किसानों और पर्यावरण दोनों के लिए भरोसेमंद विकल्प बनती जा रही हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में भी दलहन की भूमिका निर्णायक है। तेजी से बढ़ती आबादी, कुपोषण और जलवायु अस्थिरता के बीच दालें सस्ती, सुलभ और पोषण से भरपूर समाधान प्रस्तुत करती हैं। भूखमुक्त समाज, बेहतर स्वास्थ्य और टिकाऊ विकास जैसे वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने में इनका योगदान प्रत्यक्ष और प्रभावी है।

भारत में विश्व दलहन दिवस का महत्व केवल एक वैश्विक तिथि तक सीमित नहीं रहता बल्कि यह देश की कृषि परंपरा, पोषण दृष्टि और सांस्कृतिक चेतना से गहराई से जुड़ जाता है। भारत न केवल विश्व के प्रमुख दलहन उत्पादक और उपभोक्ताओं में अग्रणी है बल्कि यहां की खाद्य संस्कृति में दाल को संतुलित आहार की आत्मा माना गया है। दाल-चावल, दाल-रोटी और खिचड़ी जैसे सरल, सुलभ और पौष्टिक भोजन सदियों से भारतीय समाज में स्वास्थ्य, सादगी और सहजीवन के प्रतीक रहे हैं। दलहन केवल थाली की शोभा नहीं बल्कि पोषण सुरक्षा की मजबूत आधारशिला हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, खनिज और सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कुपोषण से लड़ने और स्वास्थ्य सुधारने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। विशेषकर शाकाहारी आबादी के लिए दालें सस्ती, टिकाऊ और भरोसेमंद प्रोटीन स्रोत हैं।

कुल मिलाकर, यह दिवस किसानों के लिए भी नई संभावनाओं का द्वार खोलता है। दलहन आधारित फसल चक्र अपनाने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटती है और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। परिणामस्वरूप किसानों की लागत कम होती है और आय में स्थिरता आती है। साथ ही, जलवायु परिवर्तन के दौर में दलहन खेती पर्यावरण के अनुकूल समाधान प्रस्तुत करती है। उपभोक्ताओं के लिए यह अवसर अपने भोजन विकल्पों पर पुनर्विचार करने का संदेश देता है, अधिक पौध आधारित, स्थानीय और पोषण-संपन्न आहार की ओर लौटने का आह्वान। दालें यह सिद्ध करती हैं कि सादगी में भी उत्कृष्टता छिपी होती है। यदि नीति-निर्माता, किसान और उपभोक्ता मिलकर दलहनों को प्राथमिकता दें तो स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था, तीनों को एक साथ मजबूती मिल सकती है। सच यही है कि छोटे-छोटे बीज मिलकर एक सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भविष्य की नींव रखते हैं।

(लेखक साढ़े तीन दशक से पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार और चर्चित पुस्तक 'प्रदूषण मुक्त सांसें' के लेखक हैं)

युवकत्व की पहचान

मनुष्य स्वतंत्र संकल्प का स्वामी होता है। उसका संकल्प जैसा होता है, व्यक्तित्व भी वैसा ही नाझमत हो जाता है। सृजन और ध्वंस के संस्कार मनुष्य के भीतर होते हैं। उन संस्कारों को वह संकल्पशक्ति के सहारे बदल सकता है। जिस व्यक्ति में विधायक भावों की प्रचुरता होता है वह ध्वंसात्मक संस्कारों को सृजनशीलता में बदल लेता है। निषेधात्मक भाव व्यक्ति को व्रूरता, हिंसा, अनुशासनहीनता, असदाचार की दिशा में प्रेरित करते हैं। जिस राष्ट्र और समाज में हिंसा का बोलबाला होता है, रास्ते चलते बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, वह उस राष्ट्र और समाज का दुर्भाग्य होता है। उस दुर्भाग्य से बचने के लिए अहिंसक शक्तियों को जगाने और संगठित बनाने की जरूरत है। यह सच है कि हिंसक वारदातें आदमी के मन में दहशत पैदा कर देती हैं। दहशत की स्थिति में कोई भी व्यक्ति न तो सही ढंग से सोच सकता है और न ही अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकता है। भयोत्पादक परिस्थितियों का प्रभाव बच्चों और वृद्धों पर अधिक होता है। युवकों में भय की मात्रा कम होती है। वे जान-बूझकर खतरों को मोल लेते हैं। उनकी मानसिकता साहसिक काम करने की रहती है, किंतु इसमें भी विवेक की अपेक्षा है। विवेक के अभाव में युवक कुछ ऐसे काम कर लेता है, जो उसे उम्र से कई वर्ष आगे ढकेल कर जर्जर बना देते हैं।

देश की युवा पीढ़ी सही अर्थ में अपने यौवन को सुरक्षित रखना चाहे और कोई कीर्तिमान स्थापित करना चाहे तो उसे प्रतिस्रोतगामी बनना होगा। अनुस्रोत में बहना सरल होता है। एक पतला-सा तिनका भी प्रवाह में बह जाता है, पर विपरीत दिशा में बहने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। भोगवादी प्रवृत्ति युग का प्रवाह है। इस प्रवाह को मोड़कर त्यागप्रधान मनोवृत्ति का निर्माण करना युवा होने की सार्थकता है। सत्य के प्रति अनास्था लोकजीवन का एक स्वर है। इस स्वर को बदल कर सत्यनिष्ठा का विकास करना युवकत्व की पहचान है।

विचार मंथन

लोकतंत्र के सर्वोच्च आसन पर उठते सवाल

(लेखक- सनत जैन)

लोकसभा अध्यक्ष का पद भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। यह वह आसन है, जो सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान एवं जिम्मेदारी का प्रतीक है। संविधान में परिभाषित है। लोकसभा का अध्यक्ष और राज्य सभा का सभापति पार्टीगत राजनीति से ऊपर उठकर सदन का संचालन करेगा। दोनों ही सदन में सभी सदस्यों के हितों के संरक्षण की जिम्मेदारी अध्यक्ष और सभापति की होती है। हालिया घटनाक्रम ने इसी धारणा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्ष द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी करना कोई साधारण राजनीतिक घटना नहीं है। संसदीय लोकतंत्र की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया है। पिछले कई सत्रों से लोकसभा में विपक्ष आरोप लगाता रहा है, उन्हें सदन में बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा। बोलने के पहले तरह-तरह से उन्हें रोका जा रहा है। सदन के अंदर सदस्यों को बोलने की जो स्वतंत्रता थी, उसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बाधित किया जा रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जैसे संवैधानिक और परंपरागत अवसर पर भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने की अनुमति न मिलना वहीं सत्ता पक्ष के एक सदस्य को बोलने का अवसर दिया गया। इसने असंतोष को आर और पार की लड़ाई में लाकर खड़ा कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष को खुली छूट दी जाती है। जबकि विपक्ष को सवालों ओर नियमों का हवाला देकर बोलने नहीं दिया जाता है। विपक्ष यह कहने से नहीं चूक रहा है, कि आसंदी द्वारा सत्ता पक्ष के लिए अलग, विपक्ष के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष का यह तर्क कि ऽसदन नियम और परंपरा से चलेगाऽ अपने आप में सही है, लेकिन सवाल यह है, कि क्या ये नियम सबके लिए समान रूप से लागू हो रहे हैं? पिछले 10 वर्षों में विपक्ष द्वारा जब भी कोई स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष को दिया गया, किसी को मंजूरी नहीं दी गई। जबकि परंपराएं और लोकसभा की कार्यवाही में ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जहां पर विपक्ष को स्थगन प्रस्ताव में बोलने का अवसर दिया गया। जब सत्ता पक्ष कांग्रेस को ऽगद्दारऽ कहता है, तब वह सदन की मर्यादा है? और जब विपक्ष उसका जवाब देना चाहता है, तब उसे ऽआउट ऑफ प्रोसीडिंगऽ बताकर रोक दिया जाता है। तो यह किस तरह की निष्पक्षता है? विपक्ष का आरोप है कि अध्यक्ष का व्यवहार निष्पक्ष एवं मध्यस्थता वाला नहीं है। ऐसा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आसंदी का व्यवहार सत्ता पक्ष के रक्षक का है। पिछले वर्षों में जिस तरह से बिल और कानूनों को बिना किसी चर्चा के हो हल्ले में पास कर दिया गया। यही कारण है कि विपक्ष ने अब अविश्वास प्रस्ताव जैसा असाधारण कदम उठाने का मन बनाया है। पिछले 76 सालों में लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तीन बार लाया गया है। चौथी बार ऐसी स्थिति बनना अपने आप में असाधारण और चिंताजनक है।

संविधान के अनुसार, अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ लिखित नोटिस आवश्यक होता है। यह प्रस्ताव तभी लाया जाता है जब विपक्ष यह मान ले कि अध्यक्ष सदन की निष्पक्षता बनाए रखने में असफल हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर एकमत हैं। महिला सांसदों ने भी लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपनी नाराजी जताई है। जो यह दर्शाता है, असंतोष केवल एक दल अथवा एक वर्ग तक सीमित नहीं है। इस पूरे विवाद का सबसे गंभीर पहलू यह है, पिछले कई वर्षों में सदन के सत्र छोटे होते जा रहे हैं। संसद की कार्यवाही बार-बार ठप्प होना अब सामान्य हो गया है। इसका लाभ उठा कर सत्ता पक्ष बिल पास कर लेती है। बजट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के बजाय बार-बार कार्यवाही स्थगित होना, अध्यक्ष द्वारा सत्ता पक्ष और विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया जाता है। जबकि नियमों के अनुसार विपक्ष की आवाज को अध्यक्ष का संरक्षण मिलना चाहिए। आसंदी की इस कार्रवाई से लोकतांत्रिक संवाद को कमजोर करता है। इतिहास गवाह है, जब-जब अध्यक्ष ने निष्पक्षता दिखाई, तब-तब विपक्ष ने भी मर्यादा का पालन किया है। जब कुर्सी की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, तब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में टकराव बढ़ता है। वर्तमान में स्थिति यहां तक पहुंच गई है, अध्यक्ष का आसन राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। वर्तमान स्थिति केवल ओम बिरला या लोकसभा अध्यक्ष के पद या बजट सत्र की नहीं है, यह उस संविधान एवं लोकतांत्रिक परंपरा की परीक्षा है जिसे भारत के संसदीय लोकतंत्र ने कई दशकों में गढ़ा गया है। यदि अध्यक्ष की निष्पक्षता पर विश्वास उठता है, तो केवल विपक्ष नहीं, पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं संविधान भी कमजोर होता है। आवश्यकता इस बात की है, लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की गरिमा को पुनः स्थापित करें। सत्ता और विपक्ष, दोनों के लिए समान नियम और समान अवसर सुनिश्चित करें। विपक्ष के पास बहुमत नहीं होता है इसलिए उसे संरक्षण की जरूरत होती है। सत्ता पक्ष की दादागिरी से अध्यक्ष ही विपक्ष को संरक्षण दे सकता है। लोकतंत्र केवल बहुमत से नहीं, बल्कि संवाद और विश्वास के सहारे चलता है।

सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर आवाम की आवाज को सदन में लेकर आते हैं। सत्ता पक्ष से ज्यादा वोट विपक्ष के पास होते हैं। विपक्ष बटा हुआ होता है, इसलिए सत्ता पक्ष राज करता है। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पंजाब नेशनल बैंक ने पांच साल की एफडी पर बढ़ाया रिटर्न

- वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा ज्यादा फायदा

मुंबई । हाल ही में रिजर्व बैंक की ब्याज दरों में कमी के बाद पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) दरों को अपडेट किया है। बैंक अब 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी सुविधा देता है। ब्याज दरें फिलहाल 3 फीसदी से शुरू होकर 7.2 फीसदी तक हैं। लंबी अवधि के निवेश के लिए 5 साल वाली एफडी उपयुक्त मानी जा रही है। आम नागरिकों को 6.10 फीसदी की दर पर 2 लाख निवेश करने पर मैच्योरिटी पर 2,70,701 रुपए मिलेंगे। यानी 70,701 रुपए का मुनाफा। 60 साल और उससे ऊपर की उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों को 6.60 फीसदी की ब्याज दर मिलेगी। इसके तहत 2 लाख रुपए की राशि 5 साल बाद 2,77,445 रुपए तक बढ़ जाएगी, जो 77,445 रुपए का शुद्ध मुनाफा है। 390 दिन वाली स्पेशल एफडी में अति वरिष्ठ नागरिकों को 7.20 फीसदी तक का रिटर्न मिलता है।

पर्पल फाइनेंस इक्विटी वारंट से जुटाएगी 69.30 करोड़

नई दिल्ली। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर्पल फाइनेंस ने हाल ही में हुई निदेशक मंडल की बैठक में 1.26 करोड़ इक्विटी वारंट जारी करने का निर्णय लिया। प्रत्येक वारंट की कीमत 55 रुपये रखी गई है, जिससे कंपनी को कुल 69.30 करोड़ रुपये जुटाने की संभावना है। यह प्रक्रिया नियामकीय अनुमोदन पर निर्भर करेगी। कंपनी ने कहा कि मौजूदा और नए निवेशकों की भागीदारी उसके कारोबारी मॉडल, प्रशासनिक ढांचे और दीर्घकालिक वृद्धि रणनीति में भरोसा दर्शाती है। इक्विटी वारंट निवेशक को भविष्य में तय कीमत पर कंपनी के शेयर खरीदने का अधिकार देता है। यानी 55 रुपये में खरीदा गया वारंट भविष्य में इसी कीमत पर शेयर लेने का अवसर देता है, चाहे बाजार भाव बढ़ जाए। कंपनी का उद्देश्य अपने विस्तार और पूंजी आधार को मजबूत करना है।

शेयर बाजार में चुनिंदा स्टॉक्स दे रहे ब्रेकआउट का संकेत

नई दिल्ली । शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच कुछ चुनिंदा स्टॉक्स निवेशकों के लिए बड़ा अवसर बनकर उभर सकते हैं। बाजार के जानकारों के अनुसार मौजूदा चार्ट पैटर्न और वॉल्यूम मूवमेंट साफ संकेत दे रहे हैं कि ये शेयर अगली तेजी के लिए तैयार हैं। बाजार के जानकारों ने कहा कि श्नाइडर इले क्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर निचले स्तरों से जबरदस्त वापसी कर चुके हैं। गिरते ट्रेंड को तोड़ते हुए शेयर ने ब्रेकआउट दिया है और सभी महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज के ऊपर मजबूती से टिक गया है। निवेशक गिरावट पर सक्रिय खरीदारी कर रहे हैं। विशेषज्ञ का सुझाव है कि इस शेयर को 769 रुपये के आसपास खरीदा जा सकता है, स्टॉप लॉस 725 रुपये रखा जाए, और लक्ष्य 850 रुपये तय किया गया है। सी नियर फार्मास्युटिकल्स लंबे समय से मजबूत अपट्रेंड में है और लगातार ऊंचे स्तर बना रहा है। फिलहाल का ठहराव कमजोरी नहीं बल्कि अगली बड़ी चाल की तैयारी माना जा रहा है। शेयर 835 रुपये के ऊपर मजबूती से बंद होने पर नई खरीदारी शुरू हो सकती है। विशेषज्ञ की राय में इसे 825 रुपये पर खरीदें, स्टॉप लॉस 780 रुपये और लक्ष्य 900 रुपये निर्धारित किया गया है। सुंदरम फाइनेंस का शेयर 5,500 रुपये के आसपास रुकावट का सामना कर रहा है, लेकिन अंदरूनी मजबूती बनी हुई है। अहम मूविंग एवरेज के ऊपर कीमतें यह दिखाती हैं कि निचले स्तरों पर लगातार खरीदारी हो रही है। अगर शेयर 5,500-5,550 रुपये के ऊपर टिकता है, तो नए रिकॉर्ड स्तर खुल सकते हैं। लक्ष्य 5,900-6,000 रुपये तय किया गया है, जबकि 5,250 रुपये को सपोर्ट और स्टॉप लॉस माना गया है।

भारत के गोल्ड ईटीएफ ने जनवरी में रिकॉर्ड 2.49 अरब डॉलर निवेश किया

- दिसंबर 2025 के 1.25 अरब डॉलर की तुलना में 98 प्रतिशत अधिक

मुंबई । जनवरी 2026 में भारत के गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) में शुद्ध निवेश 2.49 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जो दिसंबर 2025 के 1.25 अरब डॉलर की तुलना में 98 प्रतिशत अधिक है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार यह लगातार आठवें महीने निवेश में वृद्धि को दर्शाता है। 2025 में भारत के गोल्ड ईटीएफ में कुल निवेश 4.68 अरब डॉलर रहा, जो 2024 के 1.29 अरब डॉलर से 262 प्रतिशत अधिक है। इसके पहले 2023 और 2022 में निवेश क्रमशः 31 करोड़ डॉलर और 3.3 करोड़ डॉलर था। वैश्विक निवेशकों ने जनवरी 2026 में फिजिकली बैक्ड गोल्ड ईटीएफ में 19 अरब डॉलर का निवेश किया, जो अब तक का सबसे बड़ा मासिक निवेश है। सोने की कीमतों में जनवरी में 14 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 669 अरब डॉलर तक पहुंच गए। कुल होल्डिंग्स 4,145 टन तक बढ़ीं, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। एशियाई गोल्ड ईटीएफ में जनवरी में 10 अरब डॉलर का निवेश हुआ, लगातार पांचवें महीने वृद्धि दर्ज की गई। उत्तरी अमेरिका और एशिया ने वैश्विक मांग बढ़ाई, जबकि यूरोप में भू-राजनीतिक और व्यापारिक तनाव के बावजूद निवेश अच्छा रहा। महीने की शुरुआत में सोने की कीमतों में तेजी आई, लेकिन फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन के नामांकन के बाद महीने के अंत में गिरावट आई। इसके बावजूद महीने के आखिरी ट्रेडिंग दिन पर भी गोल्ड ईटीएफ में नेट पॉजिटिव फ्लो दर्ज किया गया।

रुपया 21 तेजी के साथ बंद

मुंबई । अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सोमवार को भारतीय रुपया 6 पैसे की गिरावट के साथ ही 90.71 पर बंद हुआ। आज सुबह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले शुरुआती कारोबार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 90.44 पर पहुंच गया। शुक्रवार को यह 90.65 पर बंद हुआ था। विदेशी मुद्रा बाजार में शुरुआती कमजोरी के बाद रुपये ने तेजी दिखायी। रुपए की मजबूती के पीछे सबसे बड़ा कारण भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा तैयार होना है। इस समझौते के तहत दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए कई वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करेंगे। डॉलर इंडेक्स में 0.05 फीसदी की गिरावट और घरेलू शेयर बाजार में सकारात्मक रुझान ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे समझौते और बाजार स्थिरता रुपये की मजबूती के लिए सहायक रहेगी।

वेलोसिटी एआई-आधारित 'शिपिंग' मंच के लिए 100 करोड़ का करेगी निवेश

- वेलोसिटी शिपिंग ने 2025 में शुरुआत के बाद से 900 से अधिक ब्रांड जोड़े

नई दिल्ली । ई-कॉमर्स मंच वेलोसिटी अगले दो वर्षों में अपने लॉजिस्टिक्स कारोबार वेलोसिटी शिपिंग के विस्तार के लिए 100 करोड़ रुपये निवेश करेगा। यह निवेश पूरी तरह कंपनी के आंतरिक नकद भंडार और मुख्य कारोबार से होने वाली आय से किया जाएगा। वेलोसिटी शिपिंग ने 2025 में शुरुआत के बाद से 900 से अधिक ब्रांड जोड़ लिए हैं। मासिक आधार पर ऑर्डर की मात्रा में 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जा रही है और यह वेलोसिटी की कुल आय का लगभग 40 प्रतिशत योगदान देता है। कंपनी का कहना है कि यह निवेश रणनीतिक नियुक्तियों, उत्पाद विकास और लॉजिस्टिक्स मूल्य श्रृंखला में एआई-आधारित नवाचार पर केंद्रित होगा। वेलोसिटी ने अपनी शिपिंग टीम दोगुना करने की योजना बनाई है और वरिष्ठ स्तर पर भी नियुक्तियां की हैं। वेलोसिटी शिपिंग कई तृतीय-पक्ष लॉजिस्टिक्स भागीदारों जैसे डेल्हीवरी, एकार्ट, अमेज़न, ब्लू डार्ट, ब्लिट्ज़, पिकंडेल और एक्सप्रेसबीज के साथ काम करती है। यह देशभर में 19,000 से अधिक पिनकोड क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करती है। वेलोसिटी के एक प्रमुख अे धिकारी का कहना है कि कंपनी की शुरुआत डिजिटल-प्रथम ब्रांडों के लिए पूंजी और लॉजिस्टिक्स बाधाओं को हल करने के उद्देश्य से हुई थी। 100 करोड़ रुपये का यह निवेश दीर्घकालिक रणनीति और भारत के ई-कॉमर्स परिवेश के लिए श्रेणी-निर्धारक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करने के दृष्टिकोण को दर्शाता है। स्थापित 2020 में वेलोसिटी पूंजी, लॉजिस्टिक्स, इनसाइट्स और एआई-आधारित समाधानों से जुड़ी सेवाएं प्रदान करती है, और डिजिटल-प्रथम ब्रांडों के लिए एक समग्र समर्थन नेटवर्क तैयार कर रही है।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

मुंबई । भारतीय शेयर बाजार सोमवार को तेजी के साथ बंद हुए । सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन बाजार में ये तेजी दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीददारी हावी होने से आई है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर आये साझा बयान से भी बाजार को बल मिला। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 485.35 अंक बढ़कर 84,065.75 जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 173.60 अंक उछलकर 25,867.30 पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पीएसयू बैंक, रियल्टी, इंडिया डिफेंस, मेटल, फार्मा और हेल्थकेयर के साथ करीब सभी शेयर लाभ के साथ ही उछलकर बंद हुए। सेंसेक्स पैक के शेयरों में एसबीआई, टाइटन, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, इटरनल, बीईएल, कोटक महिंद्रा बैंक, ट्रेंट, इंडिगो, एमएंडएम, एलएंडटी, अदाणी पोर्ट्स और एशियन पेंट्स के शेयर लाभ में रहे। वहीं दूसरी ओर पावर ग्रिड, आईटीसी, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, टेक महिंद्रा और मारुति के शेयरों को नुकसान हुआ। बाजार जानकारों के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर आये बयान से भी बाजार में उत्साह का माहौल है जिससे भी घरेलू बाजार उछला। भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ के 50 प्रतिशत से कम होकर 18 फीसदी होने से भी निवेशकों ने जमकर खरीदारी की । आज कारोबार के दौरान लार्जकैप के साथ ही मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी तेजी रही। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 938.45 अंक बढ़कर 60,441.15 और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 447.25 अंक बढ़कर 17,385.90 पर बंद हुआ। इससे पहले आज सुबह बाजार ने जोरदार तेजी के साथ सप्ताह की शुरुआत की। सेंसेक्स करीब 418 अंकों की तेजी के साथ 83,999 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया, जबकि निफ्टी 50 लगभग 123 अंकों की बढ़त के साथ 25,816 के आसपास खुला। निफ्टी ने 25,922 का इंट्रा-डे हाई भी छुआ, जिससे बाजार में मजबूती का संकेत मिला। वहीं एशियाई बाजारों में मजबूती, आई। जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के शेयर बाजारों की तेजी से भी भारतीय बाजार उछला। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में आई मजबूत तेजी के असर से भी भारतीय बाजार को बढ़त मिली।

भारत की जीडीपी वृद्धि 2026-27 में 6.4 फीसदी रहने का अनुमान- मूडीज

- बैंकिंग क्षेत्र की परिसंपत्ति गुणवत्ता मजबूत बनी रहेगी

नई दिल्ली ।

रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अनुमान लगाया है कि भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2026-27 में 6.4 फीसदी होगी। एजेंसी ने कहा कि मजबूत घरेलू खपत, नीतिगत उपाय और स्थिर बैंकिंग प्रणाली के कारण भारत जी-20 देशों में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करेगा। यह अनुमान वित्त मंत्रालय की 6.8-7.2 फीसदी की सीमा से थोड़ा कम है। चालू वित्त वर्ष (2025-26) में वृद्धि दर 7.4 फीसदी रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 6.5 फीसदी से अधिक है। मूडीज ने अपनी बैंकिंग प्रणाली परिदृश्य रिपोर्ट में कहा कि बैंकिंग क्षेत्र की परिसंपत्ति गुणवत्ता मजबूत बनी रहेगी। हालांकि सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) में कुछ दबाव देखने को मिल सकता है। बैंकों के पास ऋण नुकसान झेलने के लिए पर्याप्त भंडार मौजूद हैं। समूची बैंकिंग प्रणाली में ऋण वृद्धि वित्त वर्ष 2026-27 में 11-13 फीसदी रहने की संभावना है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की 10.6 फीसदी से अधिक है। मूडीज ने कहा कि सितंबर 2025 में जीएसटी का युक्तिकरण और व्यक्तिगत आयकर सीमा बढ़ाने से उपभोक्ताओं की वहन क्षमता बढ़ेगी, जिससे खपत आधारित वृद्धि को मजबूती मिलेगी। मुद्रास्फीति नियंत्रण

में रहने और वृद्धि की गति मजबूत रहने के कारण, मूडीज ने अनुमान जताया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) वित्तीरु 2026-27 में केवल तभी नीतिगत दर में ढील देगा जब आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती आएगी। वर्तमान में आरबीआई की नीतिगत दर 5.25 फीसदी है।

जनवरी में 13.68 करोड़ ईवे बिल जारी किए गए, 43 फीसदी की बढ़ोतरी

- पिछले साल जनवरी में मात्र 9.59 करोड़ ईवे बिल जारी किए गए थे

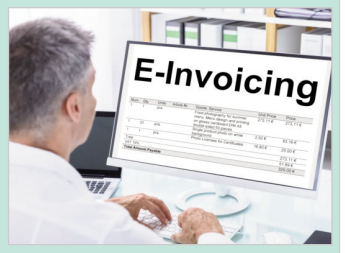

नई दिल्ली । जनवरी 2026 में देश में लगभग 13.68 करोड़ ईवे बिल जारी किए गए, जो अब तक का दूसरा सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा है। इससे पहले दिसंबर में यह आंकड़ा 13.83 करोड़ था। पिछले साल जनवरी में मात्र 9.59 करोड़ ईवे बिल जारी किए गए थे, यानी इस साल जनवरी में 43 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई। ईवे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, जो 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल की आवाजाही के लिए जीएसटी व्यवस्था के तहत अनिवार्य है। इसमें माल, भेजने वाला, प्राप्त करने वाला और ट्रांसपोर्टर का विवरण होता है। इसका मकसद कर चोरी रोकना और राज्यों में माल की रीयल-टाइम निगरानी करना है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वृद्धि जीएसटी दरों में कटौती और सरकार के नीतिगत उपायों से घरेलू खपत मजबूत होने का संकेत देती है।

बिकवाली के बावजूद भारतीय बाजार में अमेरिकी एफपीआई की हिस्सेदारी बढ़ी

नई दिल्ली ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में वैश्विक स्तर पर उथल-पुथल के बावजूद भारतीय बाजार में अमेरिकी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की हिस्सेदारी बढ़ी है। एक अखबार द्वारा डिपॉजिटरी आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार जनवरी 2025 में कुल विदेशी शेयरधारिता में अमेरिकी एफपीआई की हिस्सेदारी 39.7 प्रतिशत थी, जो जनवरी 2026 में बढ़कर 41 प्रतिशत हो गई। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब एफपीआई ने डेट और इक्विटी में मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की शुद्ध बिकवाली की। इसके बावजूद अमेरिकी एफपीआई का कुल निवेश मूल्य 29.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 32.1 लाख करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान डेट निवेश में लगभग 15,000 करोड़ रुपये और इक्विटी परिसंपत्तियों में 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। बाजार के जानकारों के अनुसार अमेरिकी एफपीआई का बड़ा निवेश लार्ज-

कैप शेयरों में है, जिनमें बीते वर्ष सीमित लेकिन सकारात्मक बढ़त रही। इसी अवधि में बीएसई सेंसेक्स 6.1 प्रतिशत चढ़ा। उन्होंने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता कम होने और अमेरिकी बाजारों की कमजोरी के चलते आगे एफपीआई की खरीदारी बढ़ सकती है।

भारत-अमेरिका ऊर्जा व्यापार, दोस्ती के बावजूद त्वरित लाभ की राह कठिन

– अमेरिका से ऊर्जा आयात में तेज़ वृद्धि करना भारत के लिए आसान नहीं होगा

नई दिल्ली । भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताओं में बढ़ती नज़दीकी को लेकर सरकार उत्साह जता रही है, लेकिन ऊर्जा क्षेत्र में इससे तत्काल और ठोस लाभ मिलने की संभावना सीमित दिखती है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में अमेरिका से ऊर्जा आयात में तेज़ वृद्धि करना भारत के लिए आसान नहीं होगा। वर्तमान में भारत अमेरिका से कच्चा तेल, एलएनजी, एलपीजी और कोकिंग कोल सहित सालाना 12 अरब डॉलर से अधिक का आयात करता है। हालांकि, माल ढुलाई की ऊंची लागत, कच्चे तेल की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतें और लंबी समुद्री यात्रा इस व्यापार को महंगा बनाती हैं। अमेरिका से तेल आने में 32 से 40 दिन लगते हैं, जबकि पहले यह अवधि 25 से 30 दिन की थी। नॉर्वे स्थित ऊर्जा अनुसंधान फर्म रायस्टैड एनर्जी के अनुसार रूस द्वारा दिए जा रहे भारी डिस्काउंट के मुकाबले अमेरिकी कच्चा तेल भारत को प्रति बैरल 12-15 डॉलर तक महंगा पड़ सकता है। इसके अलावा रूसी यूराल और अमेरिकी वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) कच्चे तेल की गुणवत्ता में बड़ा अंतर है। यूराल अधिक भारी और सल्फर युक्त है, जबकि डब्ल्यूटीआई हल्का है, जिससे दोनों को सीधे विकल्प के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस की जगह अमेरिकी कच्चा तेल लेने से भारत की रिफाइनरियों की लगभग 25 प्रतिशत क्षमता प्रभावित हो सकती है, क्योंकि उनकी संरचना भारी कच्चे तेल के अनुरूप है। भू-राजनीतिक जटिलताएं भी इस बदलाव को और कठिन बनाती हैं। भारत ने अगले पांच वर्षों में 500 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पाद खरीदने की मंशा जताई है, लेकिन ऊर्जा क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने को लेकर कोई स्पष्ट खाका अभी सामने नहीं आया है। ऐसे में अमेरिका से ऊर्जा आयात बढ़ाने की राह फिलहाल चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।

सीबीडीटी ने मसौदा आयकर नियम और फॉर्म सार्वजनिक किए

- घट जाएंगे फॉर्म और नियम, टैक्सपेयर्स को मिलेगी बड़ी राहत

नई दिल्ली ।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम, 2025 के लागू होने से पहले मसौदा नियम और फॉर्म सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किए हैं। यह अधिनियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा। सरकार के अनुसार हितधारक 22 फरवरी तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मसौदा नियमों में अनुपालन का बोझ काफी कम किया गया है। नियमों की संख्या 511 से घटाकर 333, जबकि फॉर्मों की संख्या 399 से घटाकर 190 की गई है। इसका उद्देश्य करदाताओं के लिए प्रक्रिया को सरल और सहज बनाना है। कर विशेषज्ञों के अनुसार सबसे महत्त्वपूर्ण बदलाव ट्रांसफर प्राइसिंग के खुलासे से जुड़ा है। इसके तहत फॉर्म 48 पेश किया गया है, जो पुराने फॉर्म 3सीईबी की जगह लेगा। यह फॉर्म अंतरराष्ट्रीय और कुछ विशेष घरेलू लेनदेन के खुलासे को आसान बनाएगा। पेशेवरों का कहना है कि विस्तृत खुलासों के कारण अनुपालन का बोझ बढ़ सकता है। प्राइस वाटरहाउस एलएलपी के पार्टनर जितेंद्र जैन ने कहा कि फॉर्म में उचित बाजार मूल्य की गणना, तुलनात्मक बेंचमार्क और संबद्ध उद्यमों की लागत शामिल होगी। मसौदा नियमों में वेतन के अलावा नियोक्ता से मिलने वाली सुविधाओं के आकलन और अनुपालन में भी बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं।

मियाद बढ़ने से विदेशी आय और देर से रिटर्न भरने वालों को लाभ

नई दिल्ली । केंद्रीय बजट 2026 में संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। फिलहाल करदाता को मूल रिटर्न दाखिल करने के बाद 9 महीने का समय मिलता है। नए प्रस्ताव के अनुसार यह अवधि बढ़ाकर 12 महीने या अगले कर निर्धारण वर्ष के समाप्त होने तक कर दी जाएगी, जो भी पहले हो। यह बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसलिए यह कर निर्धारण वर्ष 2026-27 से यानी वित्त वर्ष 2025-26 के रिटर्न से चलेगी। इसके मुताबिक 31 दिसंबर के बाद लेकिन 31 मार्च से पहले संशोधित रिटर्न दाखिल करने वाले करदाता पर शुल्क लगेगा।

सोना और चांदी में हफ्ते की जोरदार शुरुआत

- सोने का भाव 549 रुपए तेज, चांदी भी 9752 रुपए उछली

नई दिल्ली । इस सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सोना और चांदी के वायदा कारोबार की शुरुआत तेजी के साथ हुई। घरेलू वायदा बाजार एमसीएक्स के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी दोनों कीमती धातुओं में मजबूती देखने को मिल रही है। सोमवार को घरेलू बाजार में सोने के वायदा भाव करीब 1,58,000 रुपये, जबकि चांदी के वायदा भाव लगभग 2,62,750 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का बेंचमार्क अप्रैल कॉन्ट्रेक्ट 549 रुपये की तेजी के साथ 1,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। इसका पिछला बंद भाव 1,55,451 रुपये था। कारोबार के दौरान सोने का भाव 2,500 रुपये की बढ़त के साथ 1,57,951 रुपये तक पहुंच गया। इस दौरान सोने ने दिन का उच्च स्तर 1,58,500 रुपये और निचला स्तर 1,55,546 रुपये छू लिया। बीते महीने सोने के वायदा भाव 1,80,779 रुपये के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचे थे। वहीं चांदी के वायदा भाव में भी मजबूत तेजी देखने को मिली। एमसीएक्स पर चांदी का मार्च कॉन्ट्रेक्ट 9,752 रुपये की बढ़त के साथ 2,59,887 रुपये प्रति किलो पर खुला। इसका पिछला बंद भाव 2,49,892 रुपये था। इस समय चांदी का भाव 12,847 रुपये की तेजी के साथ 2,62,739 रुपये पर कारोबार कर रहा था। दिन के दौरान चांदी ने 2,64,885 रुपये का उच्च और 2,59,887 रुपये का निचला स्तर छुआ। इस साल चांदी का सर्वोच्च स्तर 4,20,048 रुपये प्रति किलो रहा है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

स्कॉटलैंड टी20 विश्वकप में 200 रन बनाने वाली पहली एसोसिएट टीम बनी

कोलकाता (एजेंसी)। बांग्लादेश के बाहर होने के बाद शामिल हुई स्कॉटलैंड की टीम ने टी20 विश्वकप क्रिकेट 2026 में एक नया रिकार्ड बना दिया। स्कॉटलैंड की टीम ने इटली के खिलाफ हुए मुकाबले में 207 रन बनाये और इसी के साथ ही वह 200 रन बनाने वाली पहली एसोसिएट टीम बन गयी है। इस मैच में इटली ने टॉस जीतकर स्कॉटलैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। स्कॉटलैंड ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 207 रन बनाए। इसी के साथ ही स्कॉटलैंड टी20 वर्ल्ड कप में एसोसिएट टीम के तौर पर 200 या उससे अधिक रन बनाने वाली पहली टीम बन गई है। इससे पहले यह रिकॉर्ड अमेरिकी टीम के नाम था। पिछले टी20 विश्वकप में अमेरिका ने बतौर एसोसिएट टीम कनाडा के खिलाफ सबसे अधिक 197 रन बनाए थे।

टी 20 वर्ल्ड कप में इससे पहले साल 2024 में अमेरिका ने कनाडा के खिलाफ तीन विकेट पर 197 रन बनाये थे। /3 वहीं 2024 में कनाडा ने अमेरिका के खिलाफ पांच विकेट पर 194 रन बनाये थे। वहीं 2014 में नीदरलैंड ने आयरलैंड के खिलाफ 4 विकेट पर 193 रन बनाये थे।

मैच की बात करे तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड की टीम की शुरुआत सलामी बल्लेबाज जॉर्ज मुन्से और माइकल जोन्स ने की। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 13.5 ओवर में 126 रनों की साझेदारी हुई। जॉर्ज मुन्से ने 54 गेंदों पर 13 चौके और 2 छक्के लगाकर 84 रन बनाये। वहीं जोन्स ने 30 गेंदों पर 37 रन बनाए।

वहीं नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने आये ब्रैंडन मैकमुलन ने 18 गेंदों पर 4 छक्कों की मदद से नाबाद 41 रन आये। उनका अंत में साथ माइकल लीस्क ने दिया। लीस्क ने 5 गेंदों पर 440 के स्ट्राइक रेट के साथ नाबाद 22 रन बनाए।

एशियाई चैंपियनशिप: रोमांचक शूट ऑफ में स्वर्ण पदक से चूकी मनु भाकर

नई दिल्ली (एजेंसी)। ओलंपिक की दोहरी कांस्य पदक विजेता मनु भाकर सोमवार को यहां स्वर्ण पदक जीतने के बेहद करीब पहुंचकर रोमांचक शूट ऑफ में पिछड़ गईं जिससे उन्हें एशियाई चैंपियनशिप की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक से संतोष करना पड़ा जबकि उनकी साथी भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह को कांस्य पदक मिला। महाद्वीपीय प्रतियोगिता के मौजूदा सत्र के सबसे करीब मुकाबले में से एक में स्वर्ण पदक विजेता एनगुयेन थुय ट्रेंग और मनु दोनों ने फाइनल में समान 35 का स्कोर किया। इसके बाद मुकाबला शूट ऑफ में खिंचा जिसमें वियतनाम की खिलाड़ी ने बाजी मार ली।

फाइनल में पूर्व एशियाई एयर पिस्टल चैंपियन ट्रेंग, मनु, ईशा और ओलंपियन रिदम सांगवान सभी स्वर्ण के लिए एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। ईशा ने पहली सीरीज में परफेक्ट पांच अंक से शुरुआत की जबकि मनु और ट्रेंग ने चार-चार अंक के निशाने लगाए। हर सीरीज के बाद पदक की दौड़ में स्थिति बदल रही थी लेकिन छठी सीरीज में परफेक्ट पांच के साथ वियतनाम की खिलाड़ी ने दो अंक की बढ़त बना ली। मनु और ईशा ने ट्रेंग की खराब सातवीं सीरीज का फायदा उठाया जिसमें वह सिर्फ एक निशाना लगा पाईं जिससे अंतर कम हो गया।

आठवीं सीरीज के आखिर में 30 के स्कोर के साथ आगे चल रही ईशा नौवीं सीरीज में अपने सभी शॉट चूक गईं और उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। अंतिम सीरीज में मनु ने तीन निशाने लगाए जबकि ट्रेंग दो की निशाने लगा पाईं जिससे दोनों का कुल स्कोर 35 हो गया और मुकाबला शूट ऑफ में खिंचा इससे पहले ईशा ने 'प्रिसिन' और 'ड्यूलिंग' चरण के क्वालीफिकेशन दौर में 589 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। उनके बाद मनु (584) रहीं। रिदम ने भी फाइनल में जगह बनाई जिससे आठ में से तीन निशानेबाज भारतीय थे।

ईशा, मनु और रिदम की तिकड़ी ने कुल 1,751 अंक के साथ टीम स्वर्ण जीता। चीनी ताइपे को 1,735 अंक के साथ रजत जबकि वियतनाम को 1,729 अंक के साथ कांस्य पदक मिला। जूनियर 25 मीटर पिस्टल फाइनल में नाम्या कपूर ने रोमांचक शूट ऑफ में स्वर्ण पदक जीता। विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी ने इंडोनेशिया की रिहादतुल अस्यिफा को पछाड़ा। अंजलि भागवत ने कांस्य पदक जीता। जूनियर भारतीय टीम ने इस स्पर्धा में टीम स्वर्ण भी जीता।

पाक से मैच को लेकर आईसीसी के फैसले का सम्मान करेगा बीसीसीआई : राजीव शुक्ला

मुम्बई (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा है कि पाकिस्तान के टी20 विश्वकप मैच का बहिष्कार करने के मामले में बोर्ड अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के फैसले का सम्मान करेगा। शुक्ला ने कहा है कि इस मामले में आईसीसी के जो भी फैसला लेगी। उसी का हम पालन करेगी और हमारा कोई अलग रुख नहीं होगा। शुक्ला ने कहा, मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि आईसीसी जो भी फैसला लेगा, बीसीसीआई उसी के अनुसार आगे बढ़ेगी। इस मामले में बोर्ड कुछ भी नहीं कहेगा। पाक ने बांग्लादेश को विश्वकप से बाहर किये जाने का विरोध करते हुए भारत के खिाफ विश्वकप मैच नहीं खेलने की बात कही है। वही पाक मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस मैच की संभावनाएं हैं क्योंकि लाहौर में आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम के बीच इसको लेकर एक बैठक हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, पीसीबी इस मामले पर पाकिस्तान सरकार से स्पष्ट दिशा-निर्देश लेने वाला है। इसके बाद ही उसकी ओर से कोई औपचारिक घोषणा होगी। वहीं इससे पहले पाक सरकार ने कहा था कि उसकी टीम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस फैसले को बांग्लादेश से जुड़े विवाद से जोड़ते हुए कहा कि ये बांग्लादेश के प्रति समर्थन दिखाने के लिए लिया गया है।।

इससे पहले बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों से अपने सभी मैच भारत से बाहर कराने की मांग की थी, जिसे आईसीसी ने ठुकरा दिया था। इसके बाद बांग्लादेश ने विश्वकप से नाम वापस ले लिया था। आईसीसी ने पीसीबी से यह स्पष्ट करने को कहा है कि उसने बहिष्कार का कदम क्यों उठाया है। वहीं पीसीबी ने आईसीसी को संदेश भेजा था कि सरकार के आदेशों के कारण वह इस मैच से बाहर रहेगा। आईसीसी ने पीसीबी को यह भी आगाह किया है कि यदि मैच नहीं होता है, तो इससे को भारी आर्थिक और व्यावसायिक नुकसान हो सकता है। आईसीसी ने साथ ही उसे कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। पीसीबी का मानना है कि यदि मामला कानूनी रूप लेता है, तो उनके पास मैच से बाहर रहने को लेकर अपना पक्ष रखने के मजबूत आधार है।

भारत के खिलाफ टी20 विश्वकप मैच खेलने पीसीबी ने रखीं शर्तें

लाहौर (एजेंसी)। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले आईसीसी टी20 विश्वकप मैच में खेलने को लेकर सौदेबाजी शुरु कर दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाक क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) से कहा है कि वह भारत के खिलाफ विश्व कप में खेल सकता है पर उसकी तीन मांगों को पूरा करना होगा। पीसीबी को पता है कि आईसीसी इन मांगों को मानने तैयार नहीं होगा। उसकी मांग है कि बांग्लादेश को विश्वकप से बाहर किये जाने के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए। बांग्लादेश को विश्वकप में भाग न लेने के बाद भी पार्टिसिपेशन फीस और 3- भविष्य के आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए पाकिस्तान को मेजबानी का अधिकार दिया जाए। इस रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने भी आईसीसी के सामने 2 मांगें रखी है। पहली मांग ये कि मुआवजा दो और दूसरी मांग ये कि आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी दो।

वहीं आईईसीसी के इस प्रकार की सौदेबाजी के लिए तैयार होने की संभावना नहीं है। इससे पहले पाक ने पिछले साल एशिया कप के दौरान भी टूर्नामेंट के बहिष्कार की धमकी दी थी जब भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के बाद पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने से मना कर दिया था। इस बाद उसने पूरा टूर्नोमेंट खेला था।

वहीं बांग्लादेश को पहले ही विश्वकप से बाहर कर दिया है। ऐसे में आईसीसी के उसे मुआवजा देने का सवाल भी नहीं उठाता है। आईसीसी ने हालांकि लाहौर में बीसीबी के अधिकारियों से बातचीत की। वहीं ये भी कहा जा रहा है पीसीबी में भी बोर्ड प्रमुख मोहसिन नकवी के प्रति नाराजगी है। नकवी केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं। नकवी जहां भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार पर अड़े हुए हैं वहीं पीसीबी के कुछ अधिकारी चाहते हैं कि पाकिस्तान को टी20 विश्व कप में भारत के खिलाफ मैच खेलना चाहिए।

विश्व टूर में बदलाव: इंडिया ओपन बैडमिंटन का दर्जा बरकरार, सैयद मोदी टूर्नामेंट का घटा

कुआलालंपुर (एजेंसी)। विश्व बैडमिंटन महासंघ (BWF) द्वारा सोमवार को घोषित भविष्य के कार्यक्रम में भारत का बड़ा झटका लगा है क्योंकि देश में होने वाले आयोजनों की संख्या चार से घटकर दो कर दी गई है जिसमें इस साल आयोजन संबंधी समस्याओं के बावजूद इंडिया ओपन ने अपना सुपर 750 दर्जा बरकरार रखा है लेकिन सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय सुपर 300 का दर्जा घटाकर सुपर 100 कर दिया गया।

विश्व टूर कार्यक्रम से जिन टूर्नामेंटों को हटाया गया है उनमें गुवाहाटी और ओडिशा में आयोजित सुपर 100 टूर्नामेंट शामिल हैं। इन टूर्नामेंटों को 2023 में शुरू किया गया था। लखनऊ में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय का आयोजन राष्ट्रमंडल खेल चैंपियन सैयद मोदी की स्मृति में होता है। यह साल 2018 से विश्व टूर सुपर 300 स्तर का टूर्नामेंट रहा है। 2009 में ग्रां प्री टूर्नामेंट के रूप में शुरू हुआ यह आयोजन अब अगले सत्र से सर्किट में शामिल आठ सुपर 100 टूर्नामेंटों में से एक होगा।

BWF ने सैयद मोदी टूर्नामेंट के स्तर को कम करने या ओडिशा और गुवाहाटी के टूर्नामेंटों को कैलेंडर से हटाने के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं किए हैं। दिल्ली में आयोजित होने वाले इंडिया ओपन को 2023 में सुपर 750 का दर्जा दिया गया था। वह अपनी ग्रेड दो, लेवल तीन स्थिति बनाए रखेगा और 2027-30 के नए चक्र में भी पांच सुपर 750 टूर्नामेंटों में शामिल रहेगा। इस साल इंडिया ओपन विवादों में भी रहा था। कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों ने साफ-सफाई सहित आयोजन की अन्य खामियों की ओर इशारा किया था। नए बदलावों के तहत विश्व टूर की छह-स्तरीय संरचना में 36 टूर्नामेंट शामिल होंगे। इसमें टूर्नामेंट विश्व टूर फाइनल्स, पांच सुपर 1000 टूर्नामेंट, पांच सुपर 750, नौ सुपर 500, आठ सुपर 300 और आठ सुपर 100 टूर्नामेंट शामिल हैं। खास बात यह है कि सुपर 100 टूर्नामेंट पहली बार मुख्य टूर में शामिल होंगे। सुपर 1000 स्तर के पहले चार टूर्नामेंट होते थे लेकिन अब इस स्तर के पांच टूर्नामेंट एशिया और यूरोप में आयोजित होंगे। इसमें एकल में 48 खिलाड़ी ग्रुप और फिर एलिमिनेशन चरण में प्रतिस्पर्धा करेंगे, जबकि युगल में 32 जोड़ियों का नॉकआउट ड्रॉ होगा। हर सुपर 1000 टूर्नामेंट 11 दिन तक दो सप्ताहांत में चलेगा और इसके 1,095 मैच पूरी दुनिया में प्रसारित किए जाएंगे। BWF ने बताया कि विश्व टूर में कुल वार्षिक पुरस्कार पूल लगभग 26.9 मिलियन डॉलर होगा। इसमें हर श्रेणी की पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की गयी है। BWF ने कहा, 'सुपर 1000 टूर्नामेंट के लिए 20 लाख डॉलर, सुपर 750 के लिए 11 लाख , सुपर 500 के लिए 5.60 लाख, सुपर 300 के लिए 2.90 लाख और सुपर 100 के लिए 1.40 लाख डॉलर की पुरस्कार राशि रखी गयी है।'

आईसीसी ने पीसीबी की शर्तों को मानने से इंकार किया

दुबई । अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की उन शर्तों को खारिज कर दिया है जो उसने भारत के साथ मैच खेलने के लिए रखीं थीं। इससे अब 15 फरवरी को भारत और पाक के बीच मैच होने की संभावनाएं कम हो गयी हैं। आईसीसी ने पीसीबी की मांगों को मानने से साफ मना कर दिया। पीसीबी ने आईसीसी के सामने तीन प्रमुख मांगें रखीं। पहली, भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज़ को फिर से शुरू करने की ठोस गारंटी। दूसरी आईसीसी की कुल कमाई में पाकिस्तान के हिस्से को बढ़ाने की मांग। तीसरी और अहम मांग यह थी कि भविष्य में हाथ न मिलाने जैसे घटनाक्रम दोबारा न हों और इसके लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल तय किया जाए। इसके अलावा पीसीबी ने बांग्लादेश के लिए मुआवज़ा और भविष्य के आईसीसी इवेंट्स की मेज़बानी से जुड़े मुद्दे भी उठाए।आईसीसी ने इन मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हालांकि परिषद ने यह आश्वासन ज़रूर दिया कि बांग्लादेश को आईसीसी राजस्व में उसका पूरा हिस्सा मिलेगा, लेकिन किसी भी तरह के अतिरिक्त मुआवज़े से साफ इंकार किया गया।

इटली के कप्तान मैडसेन चोटिल हुए, आगे खेलने की संभावना नहीं

कोलकाता । इटली के कप्तान वेन मैडसन टी20 विश्व कप के अपने पहले ही मैच में चोटिल होकर बाहर हो गये हैं। स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ इस मैच के चौथे ही ओवर में फ़ील्डिंग करते समय मैडसन के कंधे पर गंभीर चोट लग गयी। मैडसन उस समय मिडविकेट पर फ़ील्डिंग कर रहे थे। वह जॉर्ज मंसी के पुल शॉट को रोकने के प्रयास में गिर गये। इसके बाद उन्हें स्टेडियम से बाहर ले जाया गया। मैडसेन इटली के सबसे अनुभवी क्रिकेटर हैं। ऐसे में उनका चोटिल होना टीम के लिए करारा झटका है। वह अपना पहला विश्व कप खेल रहे हैं। उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया है। कंधे की चोट गंभीर होती है। ऐसे में उनका अब इस टूर्नामेंट में आगे खेलना संदिग्ध नजर आता है। जो बर्न्स के टूर्नामेंट के लिए चयनित नहीं होने के बाद मैडसेन को टी20 विश्व कप के लिए इटली का कप्तान बनाया गया था। इटली को इस मैच में 73 रनों से हार का भी सामना करना पड़ा है। स्कॉटलैंड ने ग्रुप सी के इस मैच में इटली को हराकर पहला मैच जीता। स्कॉटलैंड ने इस मैच में 208 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए इटली की टीम ने 16 औवर और चार गेंदों में 9 विकेट पर 134 रन ही बना पायी। ऑफ स्पिनर लीस्क ने 17 रन देकर चार विकेट लिए । इटली की ओर से बेन मानेंती ने 52 और हैरी मानेंती ने 37 रन बनाये पर वह अपनी टीम की हार नहीं टाल पाये।

टी20 विश्वकप : गेंदबाजों के कमाल के बाद बेनेट की नाबाद पारी से जिम्बाब्वे ने ओमान को हराया

कोलंबो (एजेंसी)। ब्लेसिंग मुजरबानी की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद ब्रायन बेनेट की 36 गेंद में नाबाद 48 रन की पारी से जिम्बाब्वे ने आईसीसी टी20 विश्व कप ग्रुप बी मैच में सोमवार को यहां 45 गेंद शेष रहते ओमान को आठ विकेट से शिकस्त दी। ओमान को 103 रन पर आउट करने के बाद जिम्बाब्वे ने 13.3 ओवर में दो विकेट गंवाकर 106 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की। मुजरबानी ने चार ओवर में 16 रन देकर तीन विकेट लेते हुए ओमान के शीर्ष क्रम को झकझोरा। उन्हें रिचर्ड नगारवा का (चार ओवर में 17 रन पर तीन विकेट) का अच्छा साथ मिला। एक अन्य तेज गेंदबाज ब्रैंड इवांस ने 3.5 ओवर में 18 रन पर तीन विकेट लेते हुए जिम्बाब्वे के निचले क्रम को आउट किया।

ओमान ने 27 रन पर पांच विकेट गंवा दिये थे और टीम पर काफी कम स्कोर पर आउट होने का खतरा मंडरा रहा था। विनायक शुक्ला (21 गेंद में 28 रन), सूफ्यिान महमूद (39 गेंद में 25) और नदीम खान (18 गेंद में 20) की उपयोगी पारियों से टीम ने 100 रन के आंकड़े को पार किया। इन तीनों के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज दोहरे अंक में रन बनाने में नाकाम रहा। विनायक और सूफ्यिान ने छठे विकेट के लिए 42 रन की साझेदारी कर ओमान को जल्दी आउट होने बचाया तो वहीं नदीम ने आखिरी ओवरों में कुछ बड़े शॉट के साथ टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचाने में अहम योगदान दिया।

लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे ने तेज शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज तादिवांशे मारुमनी ने 11 गेंदों में 21 रन की तेज पारी खेली, लेकिन महमूद की गेंद पर वसीम अली ने शानदार कैच लेकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। महमूद ने उसी ओवर में डियोन मायर्स को खाता खोले बिना आउट कर दिया। इसके बाद बेनेट और अनुभवी विकेटकीपर ब्रेंडन टेलर (30 गेंदों में 31 रन, रिटायर्ड हर्ट) ने तीसरे विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी कर जिम्बाब्वे को 13.3 ओवर में ही जीत दिला दी। 22 साल के बेनेट पिछले कुछ समय से शानदार लय में है। उन्होंने इससे पहले घरेलू सरजमीं पर तीन अर्धशतक और एक शतक लगाकर जिम्बाब्वे को इस विश्व कप में जगह दिलाई थी।

अनुभवी टेलर भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट्स खेलते हुए टीम को आसान जीत दिलाई। जिम्बाब्वे की टीम टी20 विश्व कप के पिछले सत्र में बाहर रहने के बाद मौजूदा टूर्नामेंट में खुद को साबित करने उतरी है। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया जिसे मुजरबानी और नगारवा ने सही साबित किया। मुजरबानी ने अपने शुरुआती दो ओवर में तीन जबकि नगारवा ने एक विकेट लिये जिससे चार ओवर के बाद ओमान का स्कोर चार विकेट पर 17 रन हो गया।

पावरप्ले के बाद गेंदबाजी के लिए आये रजा ने वसीम अली (तीन) को बोल्ड कर 27 रन तक ओमान की आधी टीम को पवेलियन की राह दिखा दी। विनायक और महमूद ने इसके बाद पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों की 42 रन की अहम साझेदारी को नगावरा ने विनायक को विकेटकीपर ब्रेंडन टेलर के हाथों कैच कराकर तोड़ा। इवांस ने महमूद की को डीप स्क्वायर लेग पर कैच कराकर ओमान को 76 रन पर आठवां झटका दिया। नदीम ने इसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ कुछ बड़े शॉट के दम पर टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचाया।

भारत के तेजस्विन ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता

-पूजा, तजिंदरपाल को रजत, पांच पदक जीतकर छठे स्थान पर रहा भारत

तिआनजिन (एजेंसी)। भारत के तेजस्विन शंकर ने चीन में आयोजित एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। शंकर ने पुरुषों की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में ये स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ ही भारतीय दल ने इस टूर्नामेंट में कुल पांच पदक जीते हैं। इस प्रकार भारतीय को पदक तालिका में छठा स्थान मिला है। वहीं मेज़बान चीन ने कुल 10 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य पदक 34 पदक के साथ ही पहला स्थान हासिल किया है। तेजस्विन ने हेप्टाथलॉन में कुल 5993 अंकों के साथ ही स्वर्ण पदक हासिल करने के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर इंडोर रिकॉर्ड भी तोड़ा। इससे पहले उनका सबसे अधिक स्कोर 5650 अंक का था, ये उन्होंने साल 2021 में अमेरिका में बनाया था ।शंकर ने इस टूर्नामेंट में पहले दिन से ही बढ़त हासिल कर ली। जो दूसरे दिन भी जारी रखी। उन्होंने 60 मीटर बाधा दौड़ के साथ ही पोल वॉल्ट और 1000 मीटर दौड़ में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया। वहीं भारत की ही पूजा ने महिलाओं की ऊंची कूद में 1.87 मीटर छलांग लगाकर रजत जबकि तजिंदरपाल सिंह तोर ने पुरुषों की शॉट पुट में 20.05 मीटर गोला फेंककर रजत पदक हासिल किया। एंसी सोजन ने लंबी कूद में 6.21 मीटर छलांग लगाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। शॉट पुट स्पर्धा में चीन के चेंगयू चेन ने 20.07 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं भारत के समरदीप सिंह गिल लंबी कूद में 18.97 मीटर छलांक लगाकर पांचवें स्थान पर रहे ।महिलाओं की लंबी कूद में भारत की मौमिता मंडल ने 6.01 मीटर की छलांग लगाकर छठा स्थान प्राप्त किया।

विश्वकप में भाग लेने नहीं मैच जीतने आयी है नेपाल टीम : पौडेल

मुम्बई । इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाली नेपाल क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित पौडेल ने कहा है कि उनकी टीम विश्वकप में एक या दो टीमों को हराने का प्रयास करेगी। नेपाल का पहले टी20 मैच में अंतिम ओवर में केवल चार रनों से हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद से ही टीम के हौंसले बुलंद हैं। टीम दो बार के विश्व चैंपियन इंग्लैंड को हराने के करीब पहुंच गयी थी पर अंतिम ओवर में वह जीत के करीब आकर भी उसे हासिल नहीं कर पायी। पोडेल के अनुसार उनकी टीम का लक्ष्य हर मैच में जीत के इरादे से उतरना रहेगा। जिस प्रकार से टीम का पहले मैच में प्रदर्शन रहा है उससे उनकी टीम का मनोबल बढ़ा हुआ है। इंग्लैंड ने रोमांचक मुकाबले में नेपाल पर बड़ी मुश्किल से केवल 4 रनों से जीत हासिल की। इस मुकाबले में उलटफेर की संभावनाएं तेज थीं पर। गेंदबाज सेम करन ने अंतिम ओवर में टीम को जीत दिला दी। इंग्लैंड के सात विकेट पर 184 रन के जवाब में नेपाल की टीम छह विकेट पर 180 रन ही बना पायी। कप्तान पौडेल ने कहा, 'खिलाड़ियों ने पहले ही मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. मुझे उन पर बहुत गर्व है। जब हम इस विश्व कप में आए थे तभी ये ठानकर आए थे कि हम यहां सिर्फ हिस्सा लेने नहीं आए बल्कि हमारा लक्ष्य जीत हासिल करना रहेगा। .हमने हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया। अंतिम ओवर में हालांकि हम सफल नहीं रहे।.'

टी20 वर्ल्ड कप में अश्विन का बड़ा रिकॉर्ड खतरे में, अर्शदीप सिंह महज इतने विकेट दूर

मुम्बई (एजेंसी)। टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन की बात करें तो समय के साथ यह सूची तेजी से बदलती नजर आ रही है। मौजूदा टूर्नामेंट में भारत के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि वह जल्द ही इस प्रतिष्ठित रिकॉर्ड के सबसे बड़े दावेदार बन चुके हैं। फ्लिहाल यह रिकॉर्ड अनुभवी ऑफस्पिनर रविचंद्रन अश्विन के नाम दर्ज है।

टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट

रविचंद्रन अश्विन - 32
अर्शदीप सिंह - 29
जसप्रीत बुमराह - 26
हार्दिक पंड्या - 24
रविंद्र जडेजा - 22

अर्शदीप सिंह रिकॉर्ड की दहलीज पर

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भारत के टी20 वर्ल्ड कप अभियानों में अहम कड़ी बनकर उभरे हैं। अब तक वह इस टूर्नामेंट में 29 विकेट चटका चुके हैं और भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने से सिर्फ3 विकेट दूर हैं। पावरप्ले और डेथ ओवर्स में उनकी सटीक यॉर्कर और स्विंग गेंदबाजी ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि कम मैचों में इस स्तर तक पहुंचना अर्शदीप की निरंतरता और अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है।

रविचंद्रन अश्विन का लंबे समय से चला आ रहा दबदबा

भारत के पूर्व मुख्य स्पिन हथियार रविचंद्रन अश्विन टी20 वर्ल्ड कप में अब तक 32 विकेट लेकर इस सूची में शीर्ष पर बने हुए हैं। कई संस्करणों में अपनी कसी हुई गेंदबाजी और अहम मौकों पर विकेट निकालने की क्षमता के दम पर अश्विन ने यह रिकॉर्ड कायम किया था। लंबे समय तक यह आंकड़ा भारतीय गेंदबाजों के लिए एक मानक बना रहा।

बुमराह और हार्दिक की अहम भूमिका

इस सूची में तीसरे स्थान पर भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं, जिनके नाम 26 विकेट दर्ज हैं। बुमराह की सटीक लाइन-लेंथ और दबाव में विकेट लेने की काबिलियत उन्हें खास बनाती है। वहीं चौथे स्थान पर ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या हैं, जिन्होंने 24 विकेट लेकर टीम को संतुलन प्रदान किया है। हार्दिक ने कई मौकों पर साझेदारी तोड़कर भारत को मैच में वापसी दिलाई है।

जडेजा और बदलती गेंदबाजी की तस्वीर

पांचवें नंबर पर अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हैं, जिनके नाम 22 विकेट हैं। जडेजा की किफायती गेंदबाजी और फील्डिंग ने भारत को कई अहम मुकाबलों में फायदा पहुंचाया है। जानकारों के मुताबिक, यह सूची दिखाती है कि भारतीय टी20 गेंदबाजी अब सिर्फस्पिन पर निर्भर नहीं रही, बल्कि तेज और स्पिन के संतुलित संयोजन की ओर बढ़ चुकी है।

आगे क्या टूटेगा रिकॉर्ड?

टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की यह सूची बदलाव के दौर से गुजर रही है। अर्शदीप सिंह का अश्विन के रिकॉर्ड के करीब पहुंचना भारतीय क्रिकेट में नई पीढ़ी के तेज गेंदबाजों के उभार का संकेत है। जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, निगाहें इस बात पर टिकी रहेंगी कि क्या अर्शदीप इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को अपने नाम कर पाते हैं या नहीं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

लंदन में टूर गाइड सेवा से मौके दे रहा भारतीय, केरल का जेम बना थॉमस टूर्स का उद्यमी

लंदन, एजेंसी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एलएसई) से मैक्रो-इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर चुके केरल के एक गांव के छात्र ने ब्रिटेन के कठिन रोजगार बाजार में साथियों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक अनूठी टूर गाइड सेवा शुरू की है। थिरुवल्ला के मल्लापल्ली निवासी जेम थॉमस मैथ्यू ने अपने दादा के नाम पर थॉमस टूर्स नाम से एक सामाजिक उद्यमी बनने का फैसला किया, जो उनके जैसे नई नौकरी चाहने वालों को अंशकालिक आधार पर लाभकारी रोजगार का मौका देता है। 23 वर्षीय जेम ने एलएसई के एक तंगहाल छात्र के रूप में सीखी अपनी बजट-अनुकूल सोच का उपयोग किया। उन्होंने ऐसे यात्रा कार्यक्रम तैयार किए, जो आगंतुकों को लंदन को स्थानीय लोगों की तरह किफायती और यादगार तरीके से घूमने का मौका देते हैं। एजेंसी जेम ने कहा, लंदन आकर मैं साइकिल चलाता रहा हूं और शहर में घूमने के कई शॉर्टकट व पैदल यात्रा सीखी। मैं शहरी स्नातकों को सशक्त बनाने के मिशन के साथ अन्य पर्यटन विकल्पों की तुलना में आधे बजट में यात्रा कार्यक्रम बनाना जानता हूं। वे छात्रों को ब्रिटेन में नौकरी खोजने की अनुमति देकर रोजगार बाजार में आगे रखना चाहते हैं। जेम थॉमस मैथ्यू की योजना सामाजिक उद्यम की अवधारणा स्नातकों को लंदन में जीवन निर्वाह के लिए 14.80 पाउंड प्रति घंटा अर्जित करने में मदद करते हुए उन्हें सम्मान दिलाने की है। वह बोले, स्नातकों को लचीलापन चाहिए ताकि वे शहर में गुजारे के लिए कमाई करते हुए औपचारिक नौकरी के लिए आवेदन कर सकें। उनका प्रयास इसमें मदद करेगा।

अमेरिका में आव्रजन कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) और संघीय आव्रजन प्रवर्तन कार्रवाइयों के खिलाफ अमेरिका में विरोध उग्र होता जा रहा है। लोग आईसीई एजेंटों के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों में चल रहे प्रदर्शनों में लोगों का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर आव्रजन कार्रवाइयों के दौरान संघीय एजेंट मानवीय मूल्यों की लगातार अवहेलना कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को मिनेसोटा राज्य के सेंट पॉल में मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज के आवास के बाहर लोगों ने व्यापक प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां व पोस्टर बैनर लेकर आईसीई एजेंटों के खिलाफ नारे लगाए और विरोध जताया। पिछले दिनों एजेंटों की गोली से एक महिला व एक पुरुष की मौत हो गई थी। इसके बाद से पूरे देश में प्रदर्शन उग्र रूप से जारी हैं।

सूडान : अर्धसैनिक समूह के हमले में 24 लोग मारे गए

खार्तूम, एजेंसी। एक कुख्यात अर्धसैनिक समूह ने शनिवार को मध्य सूडान में विस्थापित परिवारों को ले जा रहे एक वाहन पर ड्रोन से हमला करके 8 बच्चों समेत 24 लोगों की जान ले ली। युद्ध पर नजर रखने वाले डॉक्टरों के समूह डॉक्टर्स नेटवर्क ने बताया, रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) द्वारा किया गया यह हमला उत्तरी कोरदोफान प्रांत के रहाद शहर के पास हुआ। मृतकों में दो नवजात शिशु भी शामिल थे। वाहन में उत्तरी कोरदोफान में लड़ाई से भागे विस्थापित लोग सवार थे। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, इस विनाशकारी युद्ध में 40,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, लेकिन सहायता समूहों का कहना है कि यह आंकड़ा कम है और वास्तविक संख्या इससे कई गुना अधिक हो सकती है।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मेलोनी से की मुलाकात

इटली , एजेंसी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपने इटली प्रवास के दौरान मिलान में प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। वे एक सप्ताह तक दौरे पर हैं। वेंस ने ओलंपिक खेलों और कूटनीति के मुद्दों पर मेलोनी के साथ लगभग एक घंटे तक चर्चा की। मेलोनी को यूरोप में ट्रंप प्रशासन का करीबी सहयोगी माना जाता है। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में लंच भी हुआ। इससे पहले वेंस ने अपने परिवार और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ मिलानो आइस स्केटिंग एरिना में फिगर स्केटिंग प्रतियोगिता देखी।

पनामा में हचिसन का अनुबंध रद्द, हांगकांग भड़का, दूत तलब

पनामा , एजेंसी। हांगकांग के वाणिज्य प्रमुख ने शुक्रवार को पनामा के महावाणिज्य दूत को तलब कर पनामा सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की कड़ी निंदा की, जिसने हांगकांग स्थित सीके हचिसन के दो बंदरगाहों के संचालन का अनुबंध रद्द कर दिया है। इससे पहले चीन के हांगकांग और मकाऊ मामलों के कार्यालय ने पनामा को भारी कीमत चुकाने की चेतावनी दी थी। इस मामले से दोनों देशों में जबरदस्त तल्खी है।

आईएसआईएस ने इस्लामाबाद शिया मस्जिद में धमाके की जिम्मेदारी ली

इस्लमाबाद , एजेंसी। पाकिस्तान में एक्टिव आतंकी संगठन आईएसआईएस ने इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में हुए ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है। इस मामले में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में इस हमले का मास्टरमाइंड भी शामिल है। इस हमले में 31 लोग मारे गए थे और 169 अन्य घायल हो गए थे। आत्मघाती हमलावर ने खदीजा अल-कुबरा मस्जिद (इमामबाड़ा) में खुद को उड़ा लिया था। दूसरी ओर भारत ने हमले की निंदा करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने देर रात बयान जारी कर कहा कि हमले में भारत के शामिल होने का दावा निराधार है। विदेश मंत्रालय ने कहा- यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान इन मुद्दों का हल ढूंढने के बजाय, दूसरों को अपनी परेशानियों के लिए दोषी ठहरा रहा है। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा- पाकिस्तान खुद को ही धोखा दे रहा है। भारत का ये बयान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमले में भारत और अफगानिस्तान शामिल थे। हमलावर की पहचान पेशावर निवासी 32 वर्षीय यासिर के रूप में हुई, जिसने मस्जिद के गेट पर सुरक्षा गार्ड पर गोली चलाई और फिर अंदर नमाज पढ़ रहे लोगों के बीच खुद को उड़ा लिया। शुरू में 31 मौतें और

4 गिरफ्तार, मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 हुई

169 घायल होने की खबर आई, लेकिन बाद में कुछ गंभीर घायलों की मौत के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 36 हो गई। यह हमला 2008 के मैरियट होटल बम विस्फोट के बाद इस्लामाबाद में सबसे घातक हमला माना जा रहा है, जिसने राजधानी में सुरक्षा की चिंताओं को और बढ़ा दिया। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के क्षेत्रीय सहयोगी 'इस्लामिक स्टेट इन पाकिस्तान' (जिसे आईएसकेपी या आईएस-खोरासान प्रांत भी कहा जाता है) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। संगठन ने अपनी अमाक न्यूज एजेंसी और टेलीग्राम चैनल पर बयान जारी कर दावा किया कि हमलावर ने सुरक्षा गार्ड को गोली मारकर मस्जिद में प्रवेश किया और नमाजियों के निकट खुद को उड़ा लिया। यह दावा एसआईटीई इंटेलिजेंस ग्रुप जैसे संगठनों की ओर से भी पुष्ट किया गया। आईएसकेपी ने पहले भी पाकिस्तान में शिया समुदाय को निशाना बनाया है, क्योंकि वे इसे धार्मिक रूप से विरोधी मानते हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने अफगानिस्तान से जुड़े लिंक का जिक्र किया, जहां हमलावर प्रशिक्षण लेता था, लेकिन तालिबान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और इसे पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा विफलता बताया।

4 लोगों की हुई गिरफ्तारी : पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें मुख्य साजिशकर्ता भी शामिल है। एक अफगान नागरिक को भी पकड़ा गया। सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने अफगानिस्तान की धरती से हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अन्य नेताओं ने हमले की कड़ी निंदा की तथा जांच का आदेश दिया। पीड़ितों के अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए, जहां सुरक्षा चूक पर गुस्सा जाहिर किया गया। कश्मीर में शिया समुदाय ने पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन किए।

यह घटना पाकिस्तान में बढ़ते सांप्रदायिक आतंकवाद और सीमा पार से जुड़े खतरों को उजागर करती है। शिया अल्पसंख्यक पहले से ही लक्षित होते रहे हैं और यह हमला सुरक्षा एजेंसियों की चुनौतियों को और गहरा बनाता है। पाकिस्तान सरकार ने आतंकवाद विरोधी अभियान तेज करने का वादा किया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान से जुड़े नेटवर्क और आंतरिक असंतोष को संबोधित किए बिना ऐसी घटनाएं जारी रह सकती हैं।

भारी छंटनी के बाद वाशिंगटन पोस्ट के सीईओ विल लुईस ने दिया इस्तीफा, विवादों से रहा पुराना नाता

वॉशिंगटन , एजेंसी। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के पब्लिशर और सीईओ विल लुईस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब अखबार में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी की गई है। लुईस ने कहा कि अखबार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कठिन फैसले लेने पड़े। वॉशिंगटन पोस्ट ने शनिवार को बताया कि विल लुईस अखबार छोड़ रहे हैं। उन्होंने कर्मचारियों को भेजे संदेश में कहा कि उनके कार्यकाल में अखबार के लंबे समय तक टिके रहने के लिए मुश्किल फैसले जरूरी थे। लुईस ने कहा कि उनका मकसद यह था कि अखबार आने वाले कई सालों तक लाखों पाठकों तक निष्पक्ष और उच्च गुणवत्ता की पत्रकारिता पहुंचाता रहे। विल लुईस को 2023 में सीईओ बनाया गया था, जब अखबार को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा था। उन्होंने फ्रेड रयान की जगह ली थी, जो करीब एक दशक तक इस पद पर रहे।

नया अंतरिम सीईओ कौन होगा : अखबार के मुख्य वित्त अधिकारी जेफ डी'ओनोफ्रियो को अंतरिम पब्लिशर और सीईओ बनाया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक अमेजन संस्थापक जेफ बेजोस हैं। डी'ओनोफ्रियो पिछले साल जून में अखबार से जुड़े थे। इससे पहले वह गूगल और याहू जैसी कंपनियों में काम कर चुके हैं। उन्होंने कर्मचारियों को भेजे ईमेल में कहा कि आगे के फैसले पाठकों के डेटा के आधार पर लिए जाएंगे, ताकि पाठकों को वही दिया जा सके जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है।

जेफ बेजोस की प्रतिक्रिया : वॉशिंगटन पोस्ट के कर्मचारियों की यूनियन ने लुईस के इस्तीफे का स्वागत किया। यूनियन ने कहा कि उनका जाना बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यूनियन का आरोप है कि लुईस के कार्यकाल में अखबार को नुकसान पहुंचा और अब भी हालात सुधारे जा सकते हैं। यूनियन ने जेफ बेजोस से छंटनी वापस लेने या अखबार बेचने की मांग की। वहीं, जेफ बेजोस ने नेतृत्व में बदलाव को अखबार के लिए एक बड़ा अवसर बताया और कहा कि पाठक ही सफलता का रास्ता दिखाते हैं। विल लुईस का इस्तीफा ऐसे समय आया है, जब अखबार ने अपने लगभग एक-तिहाई कर्मचारियों की छंटनी की। यह छंटनी सभी विभागों में हुई। छंटनी के दौरान लुईस की गैरमौजूदगी को लेकर आलोचना हुई। अखबार के पूर्व कार्यकारी संपादक मार्टी बैरन ने इसे अखबार के इतिहास के सबसे अंधेरे दिनों में से एक बताया। लुईस के कार्यकाल में अखबार ने बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर भी खोए।

चीन का कमाल! बनाया 28 किलोमीटर का समुद्री कॉरिडोर, 20 मिनट में तय होती है 2 घंटे की दूरी

बीजिंग, एजेंसी। चीन ने शेन्जेन-झोंगशान लिंक का अनावरण किया है। यह 28 किलोमीटर लंबा एक जबरदस्त समुद्री कॉरिडोर है और इसमें 6.8 किलोमीटर लंबी पानी के अंदर सुरंग भी शामिल है।

इंजीनियरिंग की बेजोड़ मिसाल पेश करता यह सी लिंक दो शहरों के बीच यात्रा के समय को लगभग दो घंटे से घटाकर सिर्फ 20 मिनट कर देता है, जिससे ग्रेटर बे एरिया में कनेक्टिविटी बेहतर होती है। इसकी खासियत यह है कि इस कॉरिडोर में प्रीफैब्रिकेटेड सुरंग सेक्शन औरचीन का कमाल! बनाया 28 चरू का समुद्री कॉरिडोर, 20 मिनट में तय होती है 2 घंटे की दूरी एडवांस्ड वेंटिलेशन शामिल है। तूफानों और तेज लहरों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया यह लिंक इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन के लिए एक नए मानक तय करता है। ऊपर से देखने पर यह लिंक पानी के ऊपर उड़ते हुए विशाल पक्षी या समुद्र के ऊपर उड़ती हुई पतंग जैसा जैसा दिखता है। इस लिंक पर सुरक्षित यात्रा के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट

को ऑप्टिमाइज किया गया है, जिसके लिए बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित कई इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा, इंटेलिजेंट रोबोट का इस्तेमाल रोजाना इंस्पेक्शन के लिए समुद्र के नीचे बनी सुरंगों में भी किया जाता है। यह लगभग 137,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जो लगभग 19 फुटबॉल मैदानों के आकार का है और लिंगडिंगयांग के पानी में स्थित है। शेन्जेन-झोंगशान लिंक का पश्चिमी आर्टिफिशियल आइलैंड बे एरिया में एक नया समुद्री लैंडमार्क बन गया है। इस प्रोजेक्ट में पुल, द्वीप, सुरंगें और पानी के नीचे इंटरचेंज शामिल हैं। इसे पूरा होने में 14 साल से ज्यादा का समय लगा, जिसमें 15,000 से ज्यादा मजदूरों ने काम किया।

मिलान में ओलंपिक के खिलाफ भड़का जनआक्रोश, शांतिपूर्ण मार्च कैसे बना हिंसक प्रदर्शन?

मिलान, एजेंसी। इटली के शहर मिलान में शनिवार देर रात 2026 शीतकालीन ओलंपिक के खिलाफ हुआ एक प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। दिनभर शांतिपूर्ण रहा यह मार्च रात होते-होते प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में बदल गया। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस और पानी की बौछारों (वॉटर कैनन) का इस्तेमाल करना पड़ा। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार दिन के समय हजारों लोग मिलान की सड़कों पर उतरे थे। ये लोग 2026 में होने वाले विंटर ओलंपिक का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ओलंपिक के लिए हो रहा निर्माण पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है और इससे आम लोगों पर आर्थिक और सामाजिक बोझ बढ़ेगा। इस प्रदर्शन का आयोजन अनसस्टेनेबल ओलंपिक्स कमेटी नाम के समूह ने किया था। इसमें मिलान, लोम्बार्डी

और उत्तरी इटली के दूसरे इलाकों से लोग शामिल हुए।

प्रदर्शनकारियों ने इटली सरकार पर लगाए आरोप : प्रदर्शन में पर्यावरण कार्यकर्ता, छात्र, घरों के अधिकार के लिए लड़ने वाले समूह, मजदूर यूनियन, फलस्तीन समर्थक संगठन और ट्रांसफेमिनिस्ट समूह भी शामिल थे। कई प्रदर्शनकारियों ने इटली सरकार पर सख्त सुरक्षा नीतियों और नस्ली अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का आरोप भी लगाया। बता दें कि शनिवार दोपहर तक प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। लोग हाथों में हाथ डालकर चल रहे थे, गाने गा रहे थे और नाच रहे थे। लेकिन रात के समय माहौल बदल गया। जब मार्च ओलंपिक विलेज के पास पहुंचा, जहां भारी पुलिस बल तैनात था, तभी तनाव बढ़ गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने खिलाड़ियों के रहने की जगह की ओर पटाखे और धुएं के बम फेंके, हालांकि ये इमारतों तक नहीं पहुंच पाए। इसके बाद मार्च का एक हिस्सा रास्ता बदलकर विया बेनाको होते हुए पियाजाले कोर्वेटो पहुंचा। वहां मौजूद एक छोटे समूह ने पुलिस पर पटाखे फेंकने शुरू कर दिए। इसके जवाब में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर चार्ज किया और फिर पानी की बौछारों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। बाद में कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया। अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर लोग हिंसा का हिस्सा नहीं बने और वे चौक के मुख्य हिस्से में शांत खड़े रहे। इस समारोह में मशहूर इतालवी गायक आंद्रेआ बोचेली और अमेरिकी सिंगर मारिया केरी ने प्रस्तुति दी थी। इसी बीच, एक अलग घटना में उत्तरी इटली के शहर बोलोन्या में रेलवे सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं।

बांग्लादेश के टॉप हिंदू नेता और पूर्व मंत्री की हिरासत में मौत, भड़के बांग्लादेशी बोले- ये मर्डर है

ढाका, एजेंसी। जेल में बंद बांग्लादेश के पूर्व मंत्री और अवामी लीग नेता रमेश चंद्र सेन की मौत हो गई है। उन्होंने देश के शीर्ष हिंदू नेताओं में गिना जाता था, जो शेख हसीना की सरकार में जल संसाधन मंत्री रहे चुके थे। पांच बार के सांसद सेन ने साल 2024 में अपना आखिरी चुनाव जीता था। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार प्रथम आलो की रिपोर्ट के अनुसार, रमेश चंद्र सेन को शनिवार सुबह करीब 9.10 बजे तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सेन की मौत ने जेल में रखे गए अवामी लीग के सीनियर नेताओं और पूर्व मंत्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। जेल सुपरिंटेंडेंट के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि पूर्व मंत्री की तबीयत शनिवार सुबह करीब 9:00 बजे अचानक बिगड़ गई और वे बेहोश हो गए। उन्होंने तुरंत दिनाजपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए। 9.30 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 86 साल के रमेश चंद्र सेन कई बीमारियों से जूझ रहे थे। वहीं, मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, उन्हें जेल के अंदर देखभाल नहीं मिल रही थी।

हाथ में रस्सी बंधी तस्वीर हुई थी वायरल : रमेश चंद्र सेन को अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन पर हत्या समेत तीन आरोप लगाए थे। अगस्त 2024 में सेन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं, जिसमें उनके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। शेख हसीना की सरकार के बाद अवामी लीग के नेता हमलों से बचने के लिए देश छोड़कर भाग रहे थे या गुप्त जगहों पर छिप रहे थे, उस दौरान सेन ने घर पर रहना चुना। उन्हें यकीन था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है।

कौन थे रमेश चंद्र सेन : ठाकुरगांव-1 निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार सांसद रहे रमेश चंद्र सेन की गिनती देश के शीर्ष अल्पसंख्यक हिंदू नेताओं में होती थी। उनका जन्म 30 अप्रैल 1940 को ठाकुरगांव जिले के रुहिया यूनियन में हुआ था। वे 2009 से 2014 तक शेख हसीना सरकार में जल संसाधन मंत्री रहे। सेन पहली बार फरवरी 1997 में उपचुनाव जीतकर सांसद बने। बाद में वह 2008, 2014, 2018 और 2024 में सांसद बने। बांग्लादेश में रमेश चंद्र सेन की मौत को लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इस पर सवाल उठाए हैं। कुछ लोगों ने इसे हिरासत में हत्या बताया है। हिरासत में बीमार पड़ने के बाद कम से कम पांच टॉप अवामी लीग नेताओं की मौत हो चुकी है। ढाका के प्रदीप चौधरी ने फेसबुक पर लिखा, मुझे पता है कि उनके बारे में बहुत सारी झूठी बातें फैलाई जाएंगी।

तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को मिली 17-17 साल की सजा

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को अदालत ने तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराते हुए 17-17 साल की सजा सुनाई है। यह मामला विदेशी सरकार से मिले महंगे तोहफों को नियमों के खिलाफ बेचने से जुड़ा है। दोनों पर करोड़ों रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

क्या है मामला : रावलपिंडी की हाई-सिक्योरिटी अदियाला जेल में स्थित विशेष अदालत ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। जज शाहरुख अरजुमंद ने इमरान खान और बुशरा बीबी को कुल 17 साल की सजा दी। अदालत ने उन्हें पाकिस्तानी दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की अलग-अलग धाराओं में 7 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों पर 1 करोड़ 64 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने उम्र और महिला होने को देखते हुए सजा में कुछ नरमी बरतने की बात कही।

तोशाखाना-2 केस की पूरी कहानी : यह मामला 2021 में सऊदी अरब सरकार से मिले महंगे तोहफों से जुड़ा है। आरोप है कि इनमें महंगी घड़ियां, हीरे और सोने के गहनों के सेट शामिल थे, जिन्हें नियमों के अनुसार तोशाखाना में जमा नहीं किया गया। सरकार का कहना है कि इन तोहफों की असली कीमत करीब 7 करोड़ रुपये थी, लेकिन उनका मूल्यांकन सिर्फ 58-59 लाख रुपये दिखाया गया। आरोप है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने इन्हें बेहद कम कीमत पर खरीदने की कोशिश की। तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन के तहत आने वाला विभाग है, जहां विदेशी नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों से मिले तोहफे जमा किए जाते हैं। तय नियमों के तहत इन्हें बाद में खरीदा जा सकता है।

कोर्ट की कार्यवाही : इस केस में कुल 21 गवाहों ने अदालत में बयान दिए। फैसले के समय इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों अदालत में मौजूद थे। इमरान खान ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए खारिज किया। इससे पहले अक्टूबर 2024 में बुशरा बीबी और नवंबर में इमरान खान को इस केस में जमानत मिली थी। हालांकि, दोनों पहले से ही अल-कादिर ट्रस्ट केस में सजा काट रहे हैं। दोनों दोषी हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं और उनसे मुलाकात पर पिछले एक महीने से रोक लगी हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने भी उनकी जेल में हालत को लेकर चिंता जताई है।

रूस के मेडिकल कॉलेज में खूनी खेल, हॉस्टल में घुसकर चाकू से हमला, 4 भारतीय छात्र भी घायल

बश्कोर्तोस्तान , एजेंसी। रूस के बश्कोर्तोस्तान गणराज्य के एक विश्वविद्यालय में शनिवार को चाकूबाजी की घटना में कम से कम चार भारतीय छात्र भी बुरी तरह घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस हमले में कुल आठ लोगों को निशाना बनाया गया है। मीडिया में आई खबरों और यहां भारतीय मिशन की तरफ से यह जानकारी दी गई। रूस के गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रारंभिक खबरों के अनुसार, चाकू लिए एक किशोर रूस के बश्कोर्तोस्तान गणराज्य के उफा में स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्रावास में घुस गया, उसने वहां रहने वाले छात्रों पर हमला किया और उनमें से कई को चाकू मार दिया।

खुद को भी मारा चाकू : आरटीवीआई डॉट कॉम वेबपोर्टल ने यहां के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल इरिना वोल्क के हवाले से कहा, 'हमलावर ने गिरफ्तारी का विरोध किया, जिसके दौरान दो पुलिस अधिकारियों को चाकू लग गया। इसके अलावा, संदिग्ध ने खुद को भी शारीरिक नुकसान पहुंचाया।'

एक की हालत गंभीर : इसे 'दुर्भाग्यपूर्ण घटना' बताते हुए यहां स्थित भारतीय दूतावास ने कहा, 'चार भारतीय छात्रों सहित कई लोग घायल हुए हैं।' दूतावास ने कहा कि वह स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और कज़ान स्थित वाणिज्य दूतावास के अधिकारी घायल छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए उफ़ा रवाना हो गए हैं। एक विज्ञप्ति में रूसी संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमले में घायल चार लोगों को चिकित्सकीय उपचार दिया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार, इनमें से एक की हालत गंभीर है, जबकि तीन अन्य की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। 'बाजा' टेलीग्राम चैनल ने कहा कि हमलावर की पहचान 15 वर्षीय किशोर के रूप में हुई है,

जिसे गंभीर हालत में स्थानीय बच्चों के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मॉस्को से करीब 1200 किलोमीटर दूर स्थित बश्कोर्तोस्तान गणराज्य की राजधानी उफा में इस घटना की उच्च स्तरीय जांच शुरू की गई है। बाज़ा चैनल ने दावा किया कि हमलावर एक प्रतिबंधित नव-नाजी संगठन से जुड़ा था। रेन टीवी ने एम्बुलेंस वैन द्वारा घायलों को अस्पताल ले जाने के फुटेज दिखाते हुए कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, 'चारों ओर खून था।

नाबालिग था हमला करने वाला : रूस की सरकार ने बताया कि जब पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश को तो उसने जवानों पर भी हमला कर दिया। बताया गया है कि घायलों में से चार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और एक ही हालत नाजुक है। वहीं हमलावर की उम्र सिर्फ 15 साल है। उसे एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। स्थानीय प्रशासन ने घटना की जांच शुरू की है। हमले के दौरान वह होलोकॉस्ट का जिक्र कर रहा था। इसके अलावा उसने पीड़ितों के खून से दीवार पर स्वास्तिक का निशान भी बनाया। बता दें कि होलोकॉस्ट दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान लाखों यहूदियों की तहत्या को कहते हैं। एडोल्फ हिटल की नाजी पार्टी ने यहूदियों को यातना ग्रह में डाल दिया और लाखों यहूदियों की हत्या करवा दी। यूरोप में रहने वाले 10 में से सात यहूदी को मार दिया गया था। इसी सप्ताह संसद में सरकार ने बताया था कि विदेश में कितने भारतीय छात्रों की मौत हुई है। सरकार ने संसद में बताया कि 2018 से 2025 तक 17 छात्र कनाडा में और 9 छात्र अमेरिका में मारे गए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में एक छात्र की मौत हुई है। सरकार ने कहा कि विदेश में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। किसी भी घटना की जानकारी मिलते ही भारतीय दूतावास तुरंत सक्रिय हो जाता है और प्रयास करता है कि आरोपियों को सजा मिले।

आरोपी प्रतिबंधित नव-नाजी संगठन का सदस्य : रूसी संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, हमले में घायल चार लोगों का इलाज चल रहा है, जिनमें से एक की हालत गंभीर और तीन की स्थिति मध्यम बताई गई है। उफा प्रशासन ने घटना की उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी है। वहीं, टेलीग्राम चैनल 'बाजा' ने दावा किया है कि आरोपी एक प्रतिबंधित नव-नाजी संगठन से जुड़ा था। प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में बताया गया कि घटनास्थल पर चारों ओर खून फैला हुआ था और घायलों को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

बाबा सिद्दीकी हत्या मामले के आरोपी आकाशदीप को मिली सशर्त जमानत

मुंबई (एजेंसी)। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सोमवार 9 फरवरी को इस केस के आरोपी आकाशदीप करज सिंह को सशर्त जमानत दी है। आकाशदीप इस मामले में जमानत पाने वाला पहला आरोपी है। न्यायमूर्ति नीला गोखले की एकल पीठ ने जमानत देते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक आरोपी मुंबई नहीं छोड़ेगा। बता दें कि 12 अक्टूबर 2024 की रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में बाबा सिद्दीकी (66) की उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात को तीन हमलावरों ने अंजाम दिया था। मुंबई पुलिस ने इस मामले में पंजाब निवासी आकाशदीप करज सिंह (22) को नवंबर 2024 में गिरफ्तार किया था। जमानत याचिका में आकाशदीप सिंह ने खुद को निर्दोष बताते हुए दावा किया था, कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आरोपी का कहना था कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं और अभियोजन पक्ष ने हत्या में उसकी कोई विशिष्ट भूमिका स्पष्ट नहीं की है। याचिका में यह भी कहा गया कि उस पर केवल एक संगठित अपराध गिरोह का सदस्य होने का आरोप लगाया गया है, जबकि हत्या की साजिश या वारदात में उसकी सीधी संलिप्तता साबित नहीं होती। आरोपी की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में दलील दी कि इस मामले की सुनवाई निकट भविष्य में शुरू होने की संभावना नहीं है और बिना ट्रायल के लंबे समय तक जेल में रखना आरोपी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसी आधार पर जमानत की मांग की गई थी।

पटना में शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई-4 को लेकर अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया

पटना (एजेंसी)। पटना में शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई-4 को लेकर अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की शुरुआत पटना कॉलेज से हुई, जो करीब दो घंटे बाद जेपी गोलंबर पर आकर खत्म हुआ। अभ्यर्थी हाथों में 'शिक्षा मंत्री झूठा है' और 'आई लव टीआरआई-4' लिखे पोस्टर लेकर नीतिश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। इस दौरान पुलिस ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी जेपी गोलंबर तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। बैरिकेडिंग के दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच झूमाझटकी हुई। कई अभ्यर्थियों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जबकि कुछ छात्र बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। दरअसल बीपीएससी ने वर्ष 2026 तक आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है, लेकिन इसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई-4 का कोई उल्लेख नहीं है। इस बात को लेकर अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार जानबूझकर टीआरई-4 को टालना चाहती है। कैलेंडर से टीआरई-4 के गायब रहने से हजारों अभ्यर्थियों में गुस्सा और निराशा दोनों बढ़ गई है। पिछले सोमवार को जारी बीपीएससी के परीक्षा कैलेंडर में 70वीं, 71वीं और 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (सीसीई), न्यायिक सेवा, एपीओ, तकनीकी और प्रशासनिक पदों सहित 50 से अधिक भर्तियों की संभावित तिथियां दी गई हैं। इस कैलेंडर में विशेष शिक्षक, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी जैसी भर्तियों का भी जिक्र है, लेकिन टीआरई-4 पूरी तरह नदारद है।

जोधपुर दौरे पर पहुंची थाईलैंड की राजकुमारी....रातोंरात हो गया शहर का कायाकल्प

जोधपुर (एजेंसी)। थाईलैंड की राजकुमारी सिरीवनावरी नरीरत्ना राजकन्या राजस्थान के जोधपुर दौरे पर है। रविवार को जोधपुर के एयरपोर्ट स्टेशन से राजकन्या उम्मेद भवन पैलेस पहुंची यहां से रात को घंटाघर और भीतरी शहर के हवेली में पहुंची। जहां पर उन्होंने डिनर किया। सोमवार को उनका जोधपुर के मेहरानगढ़ किला जसवंत थड़ा सहित अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर जाने का कार्यक्रम है। थाईलैंड की राजकुमारी के स्वागत में जोधपुर पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। उनके जोधपुर दौरे को देखकर पुलिस ने भारी सुरक्षा और यातायात के बंदोबस्त किए गए हैं। वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर शहर में कई जगहों पर यातायात रोक दिया गया। इसके चलते लोग जाम में भी फंसे नजर आए। जहां जोधपुर के घंटाघर बाजार में भी आम दिनों में जहां अतिक्रमण और ठेलों की भीड़भाड़ रहती है। वह भी राजकुमारी के दौरे के कारण साफ सुथरा नजर आया। इस लेकर भी शहर के लोगों ने सवाल उठाए। लोगों का कहना है कि जब एक दिन में पूरी तरह से व्यवस्था बदल सकती है, तब बाकी दिनों में घंटाघर का बाजार अतिक्रमण, जाम और पार्किंग की वजह से क्यों बदहाल नजर आता है।

सोनम वांगचुक की हिरासत से जुड़े मामले में सुनवाई टली.... अब बुधवार को फैसला

नई दिल्ली (एजेंसी)। सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की हिरासत से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई बुधवार को होगी। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज ने मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने लंबी अवधि के स्थगन की मांग स्वीकार नहीं कर मामले को बुधवार के लिए सूचीबद्ध किया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से सवाल किया कि इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है। दरअसल, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति को देखकर उनकी हिरासत पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया था और केंद्र सरकार से इस संबंध में उचित निर्णय लेने को कह दिया था। केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि वांगचुक को हिरासत के दौरान बेहतर चिकित्सा सुविधा और इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्र सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। गौरतलब है कि लद्दाख में 24 सितंबर को हुई हिंसा में चार लोगों की जान गई थी। यह हिंसा लेह में लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई। करीब 90 लोग हिंसा के दौरान घायल हुए थे। बाद में, 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को लद्दाख में हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़काने के आरोप में हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में भेजा गया। इसके अलावा, प्रशासन ने चार लोगों की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया है।

क्या रूस छोड़कर अमेरिका से तेल खरीदेगा भारत, मंत्री पीयूष गोयल ने स्थिती स्पष्ट कर दी

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर देश का दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका से कच्चे तेल, एलएनजी और एलपीजी की खरीद भारत के रणनीतिक हितों के अनुकूल है, क्योंकि इससे भारत को अपने ऊर्जा संसाधनों में विविधता लाने का अवसर मिलता है। गोयल के अनुसार, व्यापार समझौते का मुख्य उद्देश्य दो देशों के बीच कारोबार के रास्ते को सुगम बनाना और प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारतीय उत्पादों को विशेष पहुंच प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 18 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क होने के बावजूद, यह समझौता भारत को अन्य विकासशील देशों के मुकाबले बढ़त दिलाता है, जो वैश्विक बाजार में भारत के प्रमुख प्रतिस्पर्धी हैं।

भारत की भविष्य की ऊर्जा और तकनीकी जरूरतों पर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने एक बड़ा लक्ष्य सामने रखा। उन्होंने कहा कि भारत को अगले पांच वर्षों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने इस आंकड़े को काफी रूढ़िवादी बताया और कहा कि 30 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखने वाले देश के लिए यह राशि बहुत कम है। गोयल ने स्पष्ट किया कि अकेले विमानन क्षेत्र के लिए ही भारत को कम से कम 100 अरब डॉलर से अधिक की आवश्यकता है। इसके अलावा, भारत वर्तमान में अन्य देशों से जो 300 अरब डॉलर का सामान आयात कर रहा है, उसे आसानी से अमेरिकी बाजार की ओर मोड़ा जा सकता है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को और मजबूती मिलेगी।

रणनीतिक पहलुओं पर बात करते हुए पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि व्यापार समझौता यह तय नहीं करता कि कौन खरीदार किससे और क्या खरीदेगा। तेल या अन्य संसाधनों की खरीद के फैसले मुख्य रूप से घरेलू खरीदारों द्वारा ही लिए जाते हैं। जब उनसे रूसी तेल की खरीद और उस पर अमेरिका के साथ हुई डील के संभावित प्रभाव के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने बहुत ही नपे-तुले अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह मामला उनके मंत्रालय के दायरे में नहीं आता और भू-राजनीतिक मुद्दों पर विदेश मंत्रालय ही बेहतर जानकारी दे सकता है। उन्होंने यह संकेत दिया कि विभिन्न मंत्रालय अपने निर्धारित क्षेत्रों में काम करते हैं और व्यापारिक समझौतों का प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक लाभ और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना होता है। दोनों देशों द्वारा जारी संयुक्त बयान के अनुसार, भारत ने अगले पांच वर्षों में अमेरिकी ऊर्जा उत्पादों, विमानों के पुर्जे, कीमती धातुओं, प्रौद्योगिकी उत्पादों और कोकिंग कोयले की खरीद में गहरी रुचि दिखाई है। यह समझौता न केवल दोनों देशों के बीच व्यापारिक घाटे को कम करने में मदद करेगा, बल्कि भारत की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा को भी सुदृढ़ करेगा। पीयूष गोयल के बयानों से यह साफ है कि भारत अपनी संप्रभुता और रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए अमेरिका के साथ एक मजबूत और दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

कोविड वैक्सीन को लेकर फैलाई गई भ्रांतियां सिरे से खारिज

नई दिल्ली (एजेंसी)। कोविड वैक्सीन और महिलाओं की फर्टिलिटी के बीच किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव का कोई प्रमाण नहीं है। लगभग 60,000 महिलाओं पर किए गए एक बड़े वैज्ञानिक अध्ययन ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर फैलाई गई भ्रांतियों को सिरे से खारिज कर दिया है। कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर शुरुआत से ही कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती रही हैं—खासकर सोशल मीडिया पर यह मिथक बार-बार दोहराया गया कि कोरोना वैक्सीन महिलाओं की प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकती है या गर्भधारण की संभावना कम कर देती है। महामारी के बाद के वर्षों में कुछ देशों, विशेषकर स्वीडन में, जन्म दर में गिरावट दर्ज की गई थी। इससे यह आशंका उभरी कि कहीं यह कमी वैक्सीनेशन की वजह से तो नहीं हुई। इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए स्वीडन की लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने विस्तृत अध्ययन किया। सोशल मेडिसिन के प्रोफेसर टॉमस टिम्पका के नेतृत्व में हुए इस शोध में स्पष्ट कहा गया कि कोविड-19 के खिलाफ एमआरएनए वैक्सीन का जन्म दर में आई कमी से कोई लेना-देना नहीं है। टिम्पका के शब्दों में, 'हमारा निष्कर्ष यही है कि वैक्सीनेशन और जन्म दर में गिरावट के बीच संबंध होने की संभावना बेहद कम है।' इस अध्ययन में वैक्सीनेटेड और नॉन-वैकसीनेटेड महिलाओं के बीच बच्चों के जन्म और गर्भपात के मामलों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं मिला। वैज्ञानिकों ने 18 से 45 वर्ष की लगभग 60,000 महिलाओं के हेल्थ रिकॉर्ड का गहन विश्लेषण किया। इनमें से 75 प्रतिशत महिलाओं को 2021 से 2024 के बीच एक या दो बार कोविड वैक्सीन लगाई गई थी। शोध में जन्म, गर्भपात, टीकाकरण और मौतों से जुड़े सभी आंकड़ों को शामिल किया गया। अध्ययन की सबसे अहम बात यह है कि इसमें सामान्य गर्भाधान और गर्भावस्था पर प्रभाव की जांच की गई, जबकि पहले की अधिकांश स्टडीज सिर्फ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करा रहे जोड़ों पर केंद्रित थीं। उम्र, पूर्व बीमारियां और अन्य कारक जो गर्भधारण को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें भी विश्लेषण में शामिल किया गया। पिछले कई अध्ययनों की तरह इस रिसर्च में भी यह तथ्य दोहराया गया कि कोविड संक्रमण गर्भवती महिलाओं के लिए अधिक खतरनाक साबित हो सकता है, जबकि वैक्सीनेशन इस जोखिम को काफी हद तक कम कर देता है।

महिला बोली सॉरी! गलती से मैसेज पहुंच गया, व्यक्ति ने शुरु की चैटिंग, गवां दिए 70 लाख

नई दिल्ली (एजेंसी)। साइबर ठगों ने एक विक्टिम के बैंक खाते से 70 लाख रुपए उड़ा दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंगलुरु स्थित प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले 50 साल के एक व्यक्ति के पास टेलीग्राम पर एक महिला का मैसेज आया। महिला ने अपना नाम प्रिया बताया, इसके बाद उसने कहा कि वह किसी राहुल नाम के व्यक्ति को मैसेज कर रही थीं और गलती से विक्टिम से पास पहुंच गया। महिला ने सॉरी कहकर मैसेज इग्नोर करने को कहा। इसके बाद विक्टिम ने चैटिंग जारी रखी। फिर दोनों के बीच वॉट्सऐप नंबर शेयर किए गए। फिर महिला ने कहा कि वह लंदन बेस्ड कंपनी में काम करती है और अपने परिवार का बिजनेस चलाती है। लंबी चैटिंग के बाद महिला ने विक्टिम का भरोसा जीत लिया।

रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने बिटकॉइन ट्रेडिंग पर चर्चा शुरू कर दी। महिला ने बताया कि बीते पांच साल में उन्होंने बिटकॉइन ट्रेडिंग से मोटी कमाई की है। इसके बाद महिला ने विक्टिम को इनवेस्टमेंट के लिए राजी कर लिया और इंस्टैंट प्रोफिट का भी वादा किया। इसके बाद विक्टिम को एक लिंक शेयर किया। विक्टिम ने जब लिंक पर क्लिक किया तो वह उसको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लेकर गया, जो देखने में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसा था। इसके बाद शख्स ने वहां अकाउंट क्रिएट किया और 9 दिसंबर को पहला इनवेस्टमेंट किया। इस इनवेस्टमेंट का अमाउंट 50 हजार रुपए था। विक्टिम ने कुछ समय इंतजार किया और उनको डैशबोर्ड पर प्रोफिट नजर आने आया। इसके बाद विक्टिम ने 8 अलग-अलग बैंक अकाउंट में 60 लाख रुपए ट्रांसपर कर दिए। इसके बाद व्यक्ति ने बैंक से लोन तक लिया और रुपये लगा दिए। विक्टिम को प्रोफिट के रूप में 2.6 करोड़ रुपये नजर आने लगे। साइबर ठगी का खुलासा तब हुआ, जब विक्टिम ने अपने प्रोफिट के रुपए निकालने की कोशिश की। इसके बाद विक्टिम के प्रयास असफल रहे।

औवेसी ने सीएम सरमा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की... वीडियो को लेकर विवाद

हैदराबाद (एजेंसी)। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग कर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर को औपचारिक शिकायत दी। औवैसी ने यह शिकायत एक कथित विवादित और अब डिलीट हो चुके वीडियो को लेकर की गई है, जिसमें सीएम सरमा को मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिख रहे है। पुलिस कमिश्नर को लिखे पत्र में ओवैसी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सरमा पिछले कई वर्षों से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सार्वजनिक भाषणों और अन्य मंचों के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयान दे रहे हैं, जिसमें से कई बयान अब भी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

हाल के महीनों में मुख्यमंत्री सरमा ने जानबूझकर अपने नफरत भरे भाषणों को और तेज किया है, जिसका साफ और सचेत इरादा मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ाना है। ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन अब्दुल्ला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में साफ तौर पर कहा है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना और राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक चरित्र, विशेष रूप से कानून के शासन की रक्षा करना राज्य और कानून लागू करने वाली एजेंसियों का संवैधानिक कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि पुलिस को औपचारिक शिकायत के अभाव में भी नफरत भरे भाषणों के मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं यह बताना चाहता हूं कि असम भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक एक्स अकाउंट द्वारा 7 फरवरी को पोस्ट किया गया हालिया वीडियो, जिस वीडियो को एक दिन बाद हटा दिया गया था लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, उसमें सरमा को हथियार से लैस दिखाया गया है और वे उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जिन्हें साफ तौर पर मुसलमान दिखाया गया है और उन्हें गोली मार रहे हैं। उक्त पोस्ट और वीडियो, उसमें इस्तेमाल की गई तस्वीरों और पॉइंट ब्लैंक शॉट और कोई दया नहीं जैसे बयानों के साथ, मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, धार्मिक समुदायों के बीच नफरत और दुर्भावना को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के इरादे से किया गया एक जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य है।

हिमालया का लिव 52 नकली बनाकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफास, 5 गिरफ्तार

गाजियाबाद (एजेंसी)। मुरादनगर पुलिस ने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह एक प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक कंपनी के नाम का दुरुपयोग कर लीवर की प्रसिद्ध दवा लिव-52 की नकली टैबलेट बनाकर बाजार में बेच रहा था। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान गिरोह के सरगना मयंक अग्रवाल सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से लगभग 50 हजार नकली टैबलेट, डेढ़ हजार खाली सफेद डिब्बियां, भारी मात्रा में रैपर और अन्य पैकेजिंग सामग्री बरामद की गई है। इस सफलता पर पुलिस टीम को 20 हजार रुपये के इनाम की घोषणा भी की गई है।

पकड़े गए आरोपियों की पहचान मोदीनगर निवासी सरगना मयंक अग्रवाल, दिल्ली निवासी अनूप गर्ग, नंदग्राम के तुषार ठाकुर व आकाश ठाकुर और निवाड़ी के नितिन त्यागी के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी नितिन त्यागी 2023 में नगर पंचायत अध्यक्ष पद का निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुका है, जबकि तुषार ठाकुर गाजियाबाद के एक मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल द्वितीय वर्ष का छात्र है। तुषार को दवाओं की तकनीकी जानकारी थी, जिसका उपयोग वह सप्लाई और कूरियर नेटवर्क संभालने में करता था।इस अवैध धंधे का

खुलासा तब हुआ जब संबंधित नामी कंपनी के प्रतिनिधियों को अलीगढ़ के बाजार में नकली दवाएं बेचे जाने की गुप्त सूचना मिली। जांच करने पर पता चला कि इन दवाओं की खेप मुरादनगर से कूरियर के जरिए भेजी गई थी। पुलिस ने कूरियर कंपनी से मिले सुरागों के आधार पर एनपी ट्रेडिंग नामक एक फर्म का पता लगाया, जिसे फर्जी तरीके से पंजीकृत कराया गया था। 3 जनवरी 2026 को इस संबंध में औपचारिक मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने साक्ष्य जुटाते हुए आरोपियों को दबोच लिया।

अभी भी गिरोह के छह अन्य सदस्य फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। पूछताछ के दौरान गिरोह के काम करने के संगठित तरीके का खुलासा हुआ। आरोपियों ने महज चार महीने पहले ही यह काम शुरू किया था। वे मेरठ से सफेद डिब्बियां और ढक्कन बनवाते थे, जबकि खैरनगर में प्रिंटिंग प्रेस के जरिए हूबहू दिखने वाले रैपर तैयार कराए जाते थे। नकली टैबलेट्स का निर्माण सोनीपत स्थित एक प्रयोगशाला में कराया जा रहा था। इन सभी सामानों को एकत्र करने के बाद मुरादनगर में इनकी पैकिंग की जाती थी। गिरोह ने जीएसटी की फर्जी बिलिंग के लिए भी अलग से इंतजाम कर रखे थे ताकि किसी को शक न हो। यह गिरोह अब तक उत्तर प्रदेश के कई जिलों जैसे अलीगढ़, मथुरा, बिजनौर, आगरा, मेरठ और शामली में 50 हजार से अधिक नकली गोलियां खपा चुका है। वे मेडिकल स्टोर संचालकों को असली दवा के बाजार भाव से 20 प्रतिशत कम कीमत पर यह माल उपलब्ध कराते थे। पुलिस अब उन मेडिकल स्टोर संचालकों की भी भूमिका की जांच कर रही है जिन्होंने कम मुनाफे के चक्कर में इन नकली दवाओं को खरीदा। डीसीपी देहात ने बताया कि बरामद दवाओं के सैंपल लैब में जांच के लिए भेज दिए गए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन नकली दवाओं में किन हानिकारक तत्वों का उपयोग किया गया था। यह मामला न केवल कॉपीराइट का उल्लंघन है, बल्कि आम जनता के जीवन के साथ किया गया एक गंभीर अपराध भी है।

खामियों से भरी मतदाता सूची से ही चुनाव कराना चाहती हैं ममता बनर्जी:भाजपा

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इस प्रक्रिया के विरोध पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) राज्य में पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है और गलतियों से भरी मतदाता सूची के सहारे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है।

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और सांसद समिक भट्टाचार्य ने राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त करना है। उन्होंने दावा किया कि सत्ताधारी दल त्रुटिपूर्ण वोटर लिस्ट के साथ चुनाव कराने के लिए बेताब है ताकि चुनावी लाभ लिया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बंगाल में हिंसा का दौर थम नहीं रहा है। भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद बड़े पैमाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुईं और महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध किए गए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां इन मामलों की जांच कर रही हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस साक्ष्यों को मिटाने के प्रयासों में जुटी है। वहीं, भाजपा के दिग्गज नेता दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने को ड्रामा करार दिया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य सरकार जब भी शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाती है, उसे हार का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनकी अपीलों का कोई ठोस कानूनी आधार नहीं होता। घोष ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार लोगों को न्याय देने में विफल रही है, जिसके कारण आम जनता को बार-बार अदालतों की शरण लेनी पड़ती है। दिलीप घोष ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण और विपक्षी दमन का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के गांवों में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और विपक्षी कार्यकर्ताओं को निरंतर प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे क्षेत्रों में विशेष समुदाय के लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भाजपा नेताओं ने पुलिस की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन टीएमसी के एक अंग के रूप में कार्य कर रहा है। इन बयानों के बाद बंगाल की राजनीति में एक बार फिर संवैधानिक प्रक्रियाओं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस छिड़ गई है।

भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता : गुजरात के उद्योगों के लिए विकास का नया द्वार

– टैरिफ में बड़ी कटौती से टेक्सटाइल, हीरा, फार्मा, केमिकल और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को मिलेगा अभूतपूर्व लाभ

अहमदाबाद (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौता किया गया है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह समझौता विशेष रूप से गुजरात के उद्योगों के लिए विकास की नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगाए गए कड़े टैरिफ को लगभग 50 प्रतिशत से घटाकर करीब 18 प्रतिशत कर दिया है। इससे अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की कीमतें अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगी और उनकी मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में गुजरात आज भारत का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य बन चुका है। राज्य में टेक्सटाइल, फार्मास्युटिकल्स, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में मजबूत औद्योगिक आधार मौजूद है। इस व्यापार समझौते से इन सभी क्षेत्रों को नया प्रोत्साहन मिलेगा। इस समझौते का सबसे अधिक लाभ टेक्सटाइल और कपड़ा उद्योग को मिलने की संभावना है। टैरिफ में कमी के चलते गुजरात के गारमेंट और होम टेक्सटाइल उत्पाद अन्य देशों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। इसके परिणामस्वरूप मध्यम अवधि में टेक्सटाइल निर्यात में 100 से 150 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। इससे राज्य के प्रमुख टेक्सटाइल क्लस्टरों में उत्पादन बढ़ेगा, अमेरिका से नए ऑर्डर प्राप्त होंगे और उद्योग की लाभप्रदता में भी वृद्धि होगी।

यह समझौता विशेष रूप से सूरत के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। दुनिया के सबसे बड़े डायमंड पॉलिशिंग हब के रूप में पहचाने जाने वाले सूरत के हीरा उद्योग को इस निर्णय से बड़ा फायदा होगा। टैरिफ में कटौती से उद्योग का मार्जिन सुधरेगा और मांग में पुनः तेजी आएगी। साथ ही, पहले उच्च टैरिफ के कारण हुए नुकसान की भरपाई होगी और अमेरिकी बाजार में हीरा उद्योग की पकड़ फिर से मजबूत होगी।

इसके अलावा, भरूच, वापी और अहमदाबाद स्थित केमिकल और फार्मा क्लस्टरों को भी इस व्यापार समझौते से बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। पहले इन क्षेत्रों के निर्यात में लगभग 25-30 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी, अब इसमें सुधार आएगा और उद्योगों को नई गति मिलेगी। कई फार्मास्युटिकल उत्पादों को शून्य या कम शुल्क का लाभ मिलने से अमेरिका जैसे रेगुलेटेड मार्केट में गुजरात की स्थिति और मजबूत होगी।

रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में, विशेष रूप से सोलर मैन्युफैक्चरिंग को इस समझौते से नया प्रोत्साहन मिलेगा। सोलर पैनल और उनके कंपोनेंट्स का उत्पादन बढ़ेगा और अमेरिका को इनका निर्यात अब व्यावसायिक रूप से अधिक लाभकारी होगा। इससे वैश्विक सप्लाई चेन में गुजरात की भूमिका और सशक्त बनेगी।

इसके साथ ही, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हस्तशिल्प और पारंपरिक कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों को भी अमेरिकी बाजार में आसान प्रवेश मिलने से बड़ा लाभ होगा। निर्यात और औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि का सीधा सकारात्मक प्रभाव राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। एमएसएमई इकाइयों, फैक्ट्रियों, लॉजिस्टिक्स और सहायक सेवाओं में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

निर्यात से जुड़े एमएसएमई सशक्त होंगे, जिससे उद्यमियों और श्रमिकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति और मजबूत बनेगी। कुल मिलाकर, भारत-अमेरिका व्यापार समझौता गुजरात के

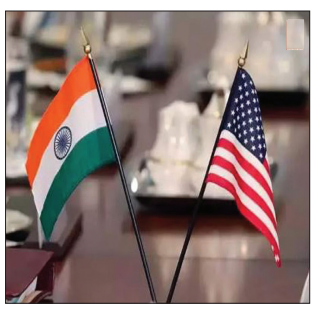

औद्योगिक विकास के लिए एक 'बूस्टर डोज' के समान सिद्ध होगा। टैरिफ में कटौती और व्यापारिक सुगमता से औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा, एमएसएमई को गति मिलेगी और गुजरात वैश्विक मूल्य श्रृंखला–विशेष रूप से उच्च मूल्य वाले अमेरिकी बाजार–में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा।